● वर्ष-2
● अंक-272
रायपुर, गुरुवार
06 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

समान नागरिक संहिता की धर्म विरोधी छवि गढ़ने में विफल रहे

आदिवासियों के बीच भ्रम फैला रहे

नयी दिल्ली। देश में इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर जमकर बहस हो रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क दिये जा रहे हैं। कोई इसे अपने धर्म के खिलाफ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि इससे हमारी संस्कृति और पहचान को खतरा हो जायेगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता संबंधी कानून का मसौदा प्रस्ताव देश के समक्ष नहीं रखा है। यानि किसी को पता नहीं है कि समान नागरिक संहिता में क्या-क्या प्रावधान होंगे लेकिन फिर भी बिना कुछ जाने समझे लोग इससे भयभीत हो रहे हैं और दूसरों के बीच भी भ्रम फैला रहे हैं। हैरत इस बात पर भी है कि पूर्वोत्तर के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए अजीबोगरीब तर्क रखे हैं। देखा जाये तो समान नागरिक संहिता के खिलाफ जो दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है वह खासतौर पर कम पढ़े लिखे या समाज के पिछड़े तबके के बीच तर्कहीन बातें पहुँचा कर चलाया जा रहा है ताकि जब भी समान नागरिक संहिता कानून बनाने संबंधी विधेयक आये तब इसका खुलकर विरोध करवाया जा सके। इसलिए जरूरत है कि जनता को जागरूक किया जाये ताकि दुष्प्रचार अभियानों की हवा निकाली जा सके।

आपत्ति नहीं है, सभी को विश्वास में लेना चाहिए-अरविंद नेताम

समान नागरिक संहिता के विरोध में जब इसकी कथित धर्म विरोधी छवि नहीं गढ़ी जा सकी तो अब कुतर्क फैलाया जा रहा है कि यह जनजातीय समाज के लिए घातक होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की संस्था %छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज (सीएसएएस) ने कहा है कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उन जनजातियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा जिनके पास अपने समाज पर शासन करने के लिए अपने स्वयं के पारंपरिक नियम हैं। सीएसएएस के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा है कि उनके संगठन को समान नागरिक संहिता पर पूरी तरह से आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्र को इसे लाने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में समान नागरिक संहिता लागू करना अव्यावहारिक लगता है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता में जन्म, विवाह और संपत्ति के लिए समान कानून बनाने का प्रस्ताव है जबकि आदिवासी समाज के लगभग सभी रीति रिवाज, परंपराएं सामुदायिक और कुल की होती हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपने जन्म, विवाह, तलाक, विभाजन, उत्तराधिकारी, विरासत और जमीन संपत्ति के मामलों में प्रथागत या रूढ़िविधि (कस्टमरी लॉ) से संचालित है और यही उसकी पहचान है जो उसे बाकी जाति, समुदाय और धर्म से अलग करती है। नेताम ने कहा कि आदिवासियों के प्रथागत कानून को संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) के तहत कानून का बल प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम के तहत कई अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज के सदियों से चले आ रहे विशिष्ट रीति-रिवाज और परंपराओं को प्रभावित करेगा,

संसद की स्थायी समिति के विचार

लगभग ऐसे ही स्वर कुछ अन्य जनजातीय संगठनों के भी रहे। संभवत: इसीलिए हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता बनने की स्थिति में पूर्वोत्तर एवं अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने की वकालत की गयी। रिपोर्टों के मुताबिक विधि से संबंधित संसदीय समिति के प्रमुख सुशील मोदी ने पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को किसी भी प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की हिमायत की। सूत्रों ने बताया है कि समिति की बैठक में इस ओर ध्यान दिलाया गया था कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बिना उनकी सहमति के केंद्रीय कानून लागू नहीं होते हैं।

विवादों का पिटारा न खोला जाए- मोइली

देश में समान नागरिक संहिता को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी, विधि आयोग एवं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया कि वे पर्सनल लॉ पर विवादों का पिटारा न खोलें तथा समाज में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा न करें। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यह मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि समाज में विभाजन पैदा किया जा सके, देश को अस्थिर किया जा सके और भारतीय समाज की विविधिता को खत्म किया जा सके। मोइली ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

अश्विनी उपाध्याय का तर्क

बहरहाल, जहां तक समान नागरिक संहिता के संभावित कानूनी पहलुओं की बात है तो इस बारे में भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि समान नागरिक संहिता किसी का अहित नहीं करेगी बल्कि यह समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करेगी। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि भारतीय नागरिक संहिता सबको समान रूप से देखने वाली होगी इसमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होने की संभावना नहीं है।

इन दिनों

✍ हिमांशु मिश्रा

कर्नाटक में महाराष्ट्र जैसा बदलाव

महाराष्ट्र में एनसीपी पर कब्जे को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की लड़ाई जारी है। इस बीच, कर्नाटक में भी सियासी उठापटक के दावे होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि एक महीने के अंदर महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर होगा। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा है कि कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है। इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या सच में कर्नाटक में सरकार गिर सकती है? अगर हां तो ये कैसे होगा? 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। इस वक्त भाजपा के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं। दोनों मिलकर भी कुल 85 के आंकड़े तक पहुंचेंगे। यह आंकड़ा 113 का काफी कम है। ऐसे में भाजपा और जेडीएस का गठबंधन होने कांग्रेस सरकार को कोई खास खतरा नहीं हैं। कुमारस्वामी और येदियुरप्पा दोनों ही महाराष्ट्र में एनसीपी की तरह कर्नाटक में कांग्रेस में फूट पड़ने का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सियासी उटलफेर संभव है। हालांकि, संख्याबल के लिहाज से ये महाराष्ट्र के मुकाबले कठिन होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक ने भी अपना समर्थन दिया है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 113 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। मतलब कांग्रेस के पास अभी बहुमत के आंकड़े से 23 सीटें अधिक हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह का बिखराव शिवसेना के साथ हुआ वैसी टूट के लिए कम से कम 90 विधायकों को बागी खेमे में आना होगा। तभी बागी गुट के विधायक दल-बदल कानून से बच पाएंगे। 2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी। कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। एक साल बाद ही कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने बगावत कर दी। बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। और राज्य में भाजपा की सरकार बनी। बागियों ने बाद में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। ज्यादातर को जीत मिली। साथ ही राज्य में भाजपा की सरकार बरकार रही। इस बार ऐसा कुछ होने के लिए बहुमत के आंकड़े को कम से कम 89 तक आना होगा। क्योंकि कांग्रेस के अलावा अन्य सभी दलों के विधायकों की संख्या 89 है। ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस के कम से कम 58 विधायक अफनी विधायकी से इस्तीफा दे दें।

अजित पवार ने पहले ही कर ली थी पूरी तैयारी

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर मचे राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग की यह प्रतिक्रिया सूत्रों के हवाले से है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग को अजित पवार गुट की चिट्ठी मिली थी। इस चिट्ठी में अजित पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का जिक्र था। वहीं, शरद पवार गुट से भी चुनाव आयोग को एक मेल गया है। इस मेल में शरद गुट ने 9 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस का जिक्र किया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि कानूनी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। एनसीपी की दोनों गुटों की ओर से हलफनामा मांगा गया है।

चुनाव आयोग ने कहा कि 30 जून 2023 को एनसीपी के विधायी और संगठनात्मक विंग के सदस्यों के भारी बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे अजीत अनंतराव पवार को एनसीपी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्षों में से एक थे और रहेंगे। सूत्रों ने यह भी कहा कि एनसीपी ने अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया और उक्त निर्णय को एनसीपी विधायकों के भारी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित भी किया गया।

सूत्रों ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनाव पैनल द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईसीआइ को 30 जून, 2023 को अजद्धत पवार से प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत एक याचिका मिली थी, जिसके बाद 30 जून को सांसदों/विधायकों/एमएलसी के 40 अजीब हलफनामे (5 जुलाई को आयोग में प्राप्त हुए) प्राप्त हुए थे। सूत्रों ने कहा कि चुनाव पैनल को सर्वसम्मति से अजित पवार को राकांपा अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव भी मिला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को महाराष्ट्र राकांपा प्रमुख जयंत आर. पाटिल की ओर से 3 जुलाई को एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कैविएट दाखिल किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में संकट बुधवार को उस समय बढ़ गया जब दोनों समूहों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक साथ बैठकें कीं।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सात जुलाई को राजधानी में होने वाली सभा से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बुधवार शाम करीब 7 बजे रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए निकल गए, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे।

प्रमुख समाचार

मोदी सरकार की गलती के चलते हुआ हादसा: जयराम

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को सरकार पर हमले को तेज करते हुए कहा कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद जवाबदेही से बचने और हेडलाइन बनाने के लिए नई थ्योरी दी गई।

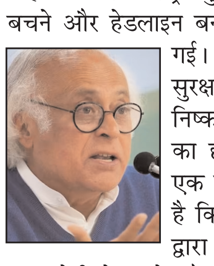

जयराम रमेश ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निष्कर्षों पर एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री द्वारा पेश की गई थ्योरी जवाबदेही से बचने और हेडलाइन बनाने के लिए है। रेल सुरक्षा आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला है कि रेल सुरक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं और प्रणालियों में गंभीर कमियों के कारण बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि लेकिन कौन सुन रहा है? वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन जारी है...मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं के कारण हुई एक भयावह त्रासदी हुई। 2 जून को बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास लूप लाइन पर चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के लौह अयस्क से भरी मालगाड़ी से टकराने के बाद हुई दुर्घटना में कम से कम 293 लोगों की मौत हो गई।

फिर मिलेंगे भाजपा और अकाली दल के हाथ

चंडीगढ़। 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तीसरी बार अपना शासन जारी रखने के लिए देश भर में अपने पूराने सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि भगवा पार्टी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। किसानों के आंदोलन के समय शिअद ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। भाजपा ने बाद में कृषि कानूनों को रद्द कर दिया लेकिन पंजाब विधानसभा चुनावों में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस दौरान भाजना ने अपने दो दशक पुराने गठबंधन के साथी को भी खो दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि भाजपा पंजाब में एक मजबूत साथी की अहमियत का एहसास हो गया है। भाजपा द्वारा दिए गए हालिया संकेत भगवा पार्टी के इरादों और संभावित गठबंधन के आह्वान को स्पष्ट करते हैं। 25 जून को चंडीगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा अकाली दल सहित पूर्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों का सम्मान करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे प्रकाश सिंह बादल की याद आती है।

बीजेपी अपने 3-4 सहयोगियों को छोड़ना चाहेगी-चिराग

नई दिल्ली। सुदूर महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जद (यू) विधायकों के साथ बैठक हुई, जिससे राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने पूछा कि क्या नीतीश भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक और वापसी के बारे में सोच रहे हैं। तेजस्वी पर ऐसे ही आरोपों को लेकर नीतीश

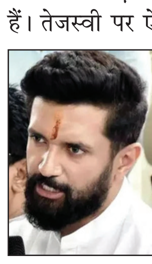

ने 2017 में राजद से नाता तोड़ लिया था। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वह कितने भी यू-टर्न ले सकते हैं। लेकिन, यह एक काल्पनिक स्थिति है और इस प्रश्न पर मेरा काल्पनिक उत्तर यह है कि भाजपा ने उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अगर फिर भी ऐसा होता है, तो यह देखना होगा कि क्या मेरे सहित नीतीश को छोड़ने वाले लोग फिर से उनके साथ आ सकते हैं। भाजपा को यह तय करना होगा कि क्या वह नीतीश को वापस पाने के लिए तीन से चार संभावित सहयोगियों को छोड़ना चाहती है।

गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का समापन करेंगे नरेंद्र मोदी

गोरखपुर। सनातन संस्कृति की पौराणिकता व ऐतिहासिकता को साहित्य के माध्यम से संरक्षित, संवर्धित करने वाली विश्व प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था गीता प्रेस की स्थापना का शताब्दी वर्ष समारोह इतिहास के पन्नों में स्वर्णाध्यायी हो जाएगा। 1923 में स्थापित गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह का औपचारिक शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल की उपस्थिति में 4 जून 2022 को किया था। अब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह होने जा रहा है। खास बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी गीता प्रेस आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। गीता प्रेस में वह आर्ट पेपर पर मुद्रित श्री शिव महापुराण के विशिष्ट अंक (रंगीन, चित्रमय) का भी विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रशासन के स्तर से सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए सीएम योगी ने मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापक दिशानिर्देश दिए थे।

चीन ने दुनिया में किए सबसे अधिक साइबर हमले

नई दिल्ली। साल 2013 यानी वो वर्ष जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) पहल की घोषणा की। जिसके बाद चीन ने कई पहल शुरू की हैं। 8 सितंबर 2020 को बीजिंग ने डेटा सुरक्षा पर वैश्विक पहल शुरू की। सितंबर 2021 में वैश्विक विकास पहल का अनावरण किया गया। अप्रैल 2022

में शी ने एशिया के लिए बोआओ फोरम के दौरान वैश्विक सुरक्षा पहल की घोषणा की। इस साल 16 मार्च को चीन ने वैश्विक सभ्यता पहल शुरू की। जिनपिंग की वन बेल्ट वन रोड ने काफी और परियोजनाओं के मुकाबले काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरी हैं। इसके वनस्पद जीआईडीएस पर सबसे कम ध्यान दिया गया। इसका श्रेय चीन द्वारा इस पर खर्च किए गए तुलनात्मक रूप से कम प्रयास को दिया जा सकता है। लेकिन चीन पर नजर रखने वाले इस बात से सहमत होंगे कि बीजिंग एक बार वहां कुछ कर देता है, तो वह हमेशा के लिए होता है। इसका एक उदाहरण द्वितीय द्वीप श्रृंखला पर चीन का दावा है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा से गायब हो गया है। हाल ही में प्रशांत द्वीप देशों पर चीन के बढ़ते फोकस को उन देशों को ताइवान से दूर करने के अलावा, उस दावे के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है।

अपनी नकारात्मकता से छुटकारा पाए कांग्रेस

अभय कुमार दुबे

आजकल कांग्रेस के प्रवक्तागण मीडिया-मंचों पर आक्रामक रवैया दिखाते हुए ऐसे हर नेता, समीक्षक या राजनीतिक ताकत को भाजपा-समर्थक बताते नजर आते हैं, जो राहुल गांधी की भूरि-भूरि प्रशंसा नहीं करता। ऐसा लगता है कि उन्होंने साफ तौर पर मान लिया है कि देश की राजनीति दो भागों में बंट गई है। एक तरफ भाजपा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है। जहां तक क्षेत्रीय शक्तियों का सवाल है, ऐसे कांग्रेसियों की मान्यता है कि वे अंतत- कांग्रेस के साथ आने के लिए मजबूर हो जाएंगी। कांग्रेस के इस हालिया रवैये को कड़ी समीक्षा की कसौटियों पर कसने की जरूरत है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट करने से समीक्षा की शुरुआत की जा सकती है। आइए, पहले सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित करें।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और दो विधानसभा चुनावों की जीत निश्चित रूप से इस पार्टी में एक नई जान फूंक चुकी है। उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अब भाजपा से दबते हुए नहीं दिखाई देते। यात्रा के दौरान ही पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे कांग्रेस का संगठन पटरी पर लौटता हुआ दिखने लगा है। मसलन, खड़गे पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और नेताओं के असंतोष और झगड़ों को निबटाने के लिए तत्पर रहते हैं। राहुल गांधी की अध्यक्षता और उसके बाद यह काम कांग्रेस के भीतर तकरीबन बंद हो गया था। दूसरे, खड़गे राज्यों के स्तर पर पार्टी की गुटबाजी का शमन करने में भी लगे हुए हैं। इसके तीन-चार उदाहरण हमारे सामने हैं।

उन्होंने कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सुलह कराई जिसके कारण पार्टी एकताबद्ध होकर चुनावी मुहिम चला पाई। जीतने के बाद भी यह खड़गे ही थे

जिन्होंने शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनने के लिए मना लिया। उसी तरह खड़गे छत्तीसगढ़ में खड़गे जूदेव और भूपेश बघेल के बीच तालमेल कायम करने में सफल रहे। इससे पहले इन दोनों के बीच तकरार की स्थिति थी। इस समय जूदेव उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और लगता है कि बघेल के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। उधर खड़गे राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद को सौम्य बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने आलाकमान की तरफ से सबसे पहले गहलोत की सर्वोच्चता को स्थापित किया। जब एक बार स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में गहलोत के नंबर-वन होने पर कोई संदेह नहीं है तो पायलट को भी लगने लगा कि उनके विद्रोह का फिलहाल कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह सही है कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ जैसी एकता नहीं बन पाई है, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तलवारें म्यान में जरूर डाल ली हैं।

यहीं हम हिमाचल प्रदेश को नहीं भूल सकते। वहां खड़गे के नेतृत्व में जिस तरह से दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और बेटे की दावेदारी को नकार कर सुक्खू को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया, उससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस आलाकमान भविष्य की तरफ भी देखने लगा है।

इन सफलताओं और सकारात्मकताओं का श्रेय निश्चित रूप से कांग्रेस को दिया जाना चाहिए लेकिन, इसी जगह के बाद से नकारात्मकताएं शुरू हो जाती हैं

पहली और बड़ी नकारात्मकता यह है कि कांग्रेस ने संघवाद के मसले पर चुप्पी साधी हुई है। कोई भी देख सकता है कि भाजपा सरकार ने किस तरह राज्यपालों और राजभवनों का सहारा लेकर गैरभाजपा सरकारों का जीना दूभर कर रखा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर राज्य की जनता ने विधानसभा में भाजपा को न चुना तो उसे केंद्र की तरफ से खुले असहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन कांग्रेस इस प्रश्न को उठाने से परहेज करती हुई दिखती है।

जाहिर है कि संघवाद के सवाल पर उसका अपना इतिहास भी गड़बड़ है, लेकिन आज वह उस इतिहास से काफी दूर आ चुकी है। उसे क्षेत्रीय ताकतों का नेतृत्व अगर करना है तो समझना होगा कि दिल्ली में अध्यादेश का सवाल आम आदमी पार्टी का मसला न होकर एक चुनी हुई सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है। उसे यह भी समझना होगा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई हो या पंजाब के राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने में डाला गया विघ्न हो- दिल्ली समेत ये सभी सवाल संघवाद के सवाल हैं।

दूसरी बड़ी नकारात्मकता यह है कि कांग्रेस भाजपा के 'हार्ड हिंदुत्व' के मुकाबले अपने 'सॉफ्ट हिंदुत्व' का प्रलोभन नहीं छोड़ पा रही है। इसी चक्कर में वह अपने इतिहास को सांप्रदायिकता की दुर्गंध से गंधा चुकी है। चाहे ताले खुलवाने की घटना हो, चाहे इंदिरा गांधी द्वारा मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करने का प्रकरण हो या राजीव गांधी द्वारा अयोध्या से अपना चुनावी अभियान शुरू करना हो - इतिहास के इन तमाम प्रकरणों में कांग्रेस हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए जमीन साफ करते हुए नजर आती है। कांग्रेस को इन मसलों पर एक सामरिक चुप्पी साधने का रवैया अपनाना होगा और कोशिश करनी होगी कि वह भाजपा द्वारा तय किए गए एजेंडे पर चलती हुई नजर न आए।

ईनामी मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार, आईईडी विस्फोट की घटना में था शामिल

बीजापुर। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को दो बड़ी सफलता मिली है। पहली सफलता में पुलिस ने पामेड़ चेरला मार्ग पर गश्त के दौरान ईनामी नक्सली मिलिशिया सदस्य को पकड़ा है। इसके साथ ही बीजापुर थाना क्षेत्र के ईसुलनार के जंगलों में नक्सल कैम्प को पुलिस बल ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने का दावा किया है।

पुलिस थाना पामेड़ एवं केरिपु 151 की संयुक्त पार्टी पामेड़ चेरला मार्ग पर एमसीपी कार्रवाई करने निकली थी। इसी दौरान सुरक्षाबलों ने 10 हजार रुपये के ईनामी नक्सली मिलिशिया सदस्य मड़कम जोगा उम्र 21 वर्ष को पकड़ लिया। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ थाना पामेड़ में केस दर्ज कर न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया है। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार नक्सली थाना पामेड़ क्षेत्र में 30 सितंबर 2022 को धरमावारम जाने वाली कच्ची सड़क पर आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल था। जिसमें 01 जवान शहीद हुआ था। पकड़े गये माओवादी मिलिशिया सदस्य के खिलाफ थाना पामेड़ में 01 स्थाई वारंट भी लंबित है।

ईसुलनार के जंगलों में नक्सली कैम्प तबाह

बीजापुर थाना क्षेत्र ईसुलनार के जंगलों में नक्सली कैम्प को पुलिस बल ने तबाह कर दिया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों के सामान बरामद किये हैं। साथ ही कुछ नक्सलियों के मारे जाने का पुलिस ने दावा किया है। घटनास्थल पर झाड़ियों एवं पत्तों में खून के धब्बे एवं आसपास घसीटने के निशान मिले हैं। जिससे 3-4 नक्सली के मारे जाने की संभावना है। जिसके बाद पुलिस ने मौके से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर 20 मीटर, डेटोनेटर-04, जिलेटिन 08, बैटरी 12, सोलर प्लेट, पिट्ठू बैग, माओवादी साहित्य और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की।

नक्सली फरमान के बाद सीआरपीएफ जवानों के दो परिवार खेती, मकान और मवेशी छोड़कर जाने के लिए हुए मजबूर

बीजापुर। जिले की पुलिस और शासन यह दावा करते थकते नही हैं कि नक्सली कमजोर पड़ गये हैं, और उसे काफी पीछे ढकेल दिया गया है। इपके ठीक विपरीत जिले के नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों की दहशत बढ़ती जा रही है। नक्सलियों ने दो सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को गांव छोडऩे का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद दोनों परिवार के करीब 11 सदस्यों ने गांव छोड़ दिया है। इस घटना से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सीआरपीएफ जवान के परिवार बीजापुर में सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की स्थिति कैसी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में कुटरू इलाके के दरबा गांव के दो परिवार के दो युवकों का चयन सीआरपीएफ में होने के बाद दोनों युवकों को ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। इस बीच नक्सलियों ने उनके परिवार के एक सदस्य का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए, फिर गांव छोडऩे का तालीबानी फरमान सुना दिया, जिससे डरकर पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ दिया है।

विदित हो कि इनके पास करीब 8 एकड़ खेती की जमीन, मकान और मवेशी थे, सबको छोड़कर चले गए। नक्सलियों ने दोनों युवकों के सीआरपीएफ में भर्ती होने का विरोध किया, इसके साथ ही उन्हें इस गांव में खेती किसानी नहीं करने की हिदायत देते हुए नक्सलियों ने कहा कि आपक।भाई सीआरपीएफ में भर्ती हुए हैं, इसलिए आप लोग यहां नहीं रह सकते, अगर आप लोग यहां रहेंगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। आप लोग गांव छोड़ दीजिए, इस गांव में आपको नहीं आना है। बीजापुर एसडीओपी पुलिस विकास ने बताया कि इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है, थाने में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। हमने सीआरपीएफ जवानों के पीड़ित परिवार को पुलिस कैंप के आस-पास रहने की सलाह दी है, लेकिन जवानों के पीड़ित परिवार वालों ने अपने परिजन के यहां दंतेवाड़ा जाने का फैसला लिया है।

नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के छात्रों ने नीट जेईई में सफलता हासिल की

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले छात्रों ने अपने मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया है। दंतेवाड़ा जिले के कुल 68 स्टूडेंट्स ने नीट और जेईई 2023 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस अवसर पर बोलते हुए दंतेवाड़ा कलेक्टर विनित नंदनवार ने स्टूडेंट्स की इस कामयाबी को एक प्रमुख उपलब्धि बताया है।दंतेवाड़ा कलेक्टर विनित नंदनवार ने कहा, छू लो आसमान, जिले में काम करने वाला एक संगठन है। जो ग्राम बालूद और कारली में काम कर रहा है। छात्रों को परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रश्नों को हल करने की रणनीति के बारे में सिखाया जाता है। यहां के 65 छात्रों ने स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) पास करने में सफलद्यता हासिल की हैं। यह एक प्रमुख उपलब्धि है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनित नंदनवार ने कहा कि यह महसूस करते हुए कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, एक ड्रॉपआउट बैच शुरू किया गया। जिसके परिणामस्वरूप कई छात्रों का चयन हुआ। हालांकि उन्हें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इस बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए जिले में छात्रों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। वर्तमान में 239 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 660 छात्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) प्रमोद ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। जिला प्रशासन की मदद से दंतेवाड़ा में दो कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में छात्रों (9वीं से 12वीं तक) को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जा रही है। लड़कों के लिए कोचिंग ग्राम बालूद में और लड़कियों के लिए कोचिंग ग्राम कारली में संचालित किया जाता है। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा, एनईईटी और जेईई की तैयारी के लिए विषय विशेषज्ञ भी हैं।

सिम्स मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। जिसका असर बिलासपुर में देखा जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में भी मरीज परेशान हैं। इलाज नहीं मिलने के कारण सिम्स आने वाले गरीब मरीज अब निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं।

आपको बता दें कि मंगलवार से प्रदेश के लगभग 50 हजार स्वास्थ्यकर्मी अपनी लंबित मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। जिसके कारण संभाग के सभी स्वास्थ्यकर्मी 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर शासन को अवगत कराया है, लेकिन शासन ने सिर्फ आश्वासन दिया।मांगें पूरी होती नहीं देख अब स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल का सहारा ले रहे हैं।

स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ने लगा है। हड़ताल के कारण सिम्स अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। नर्सों के नहीं होने के कारण एडमिट मरीजों को दवाईयों के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।वहीं एक्सरे,पैथॉलोजी और ईसीजी के मरीजों की जांच भी अटकी हुई है। लिहाजा मरीजों को निजी सेंटर्स में जांच के लिए

जाना पड़ रहा है।

नीरज शिंदे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मरीजों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन अभी तो वह जैसे तैसे व्यवस्था बना रहे हैं, यदि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी रहेगी तो आने वाले दिनों में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल में हो रही दिक्कतों की जानकारी उन्होंने डीएमई कार्यालय में दी है, और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बरकरार रखी जाए।

सिम्स मेडिकल कॉलेज में कौन सी सेवाएं हुई बाधित

सेंट्रल लैब पैथोलॉजी- हेमोग्लोबिन, सम्पूर्ण ब्लड सेल जांच, ई।एस।आर।, ब्लड ग्रुप, परिफेरल स्मीयर, मलेरिया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जैसे महत्वपूर्ण जांच की मशीन चलाने वाला कोई नही है। पहले एक दिन में 1200 जांच होती थी, आज 500 नहीं हो पाई है।

पैथोलॉजी कॉलेज- हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच मरीजो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें कैंसर जैसे कारणों एवं बीमारी का पता चलता है पूर्णत: बंद है। फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच जिनमे पोस्टमार्टम के विसरा जांच के लिए महत्वपूर्ण है जो कि आपराधिक प्रकरण की भी जांच की जाती है समस्त जांच मानवधिकार से भी संबधित है। समस्त जांच पूर्णत: बंद है।

साइटोपैथोलॉजी जांच जिसमे एफएनएसी जैसे महत्वपूर्ण जांच जिसके जांच के बाद मरीजो का उपचार चालू किया जाता है पूर्णत: बंद है। स्पेशल हेमाटोलॉजी के समस्त स्पेशल जांच एवं यूरिन 24 घंटे की समस्त प्रकार की जांच बंद है। कॉलेज में एमबीबीएस के स्टूडेंट की पढ़ाई हेतु प्रायोगिक क्लासेस बंद है।

बायोकेमिस्ट्री हॉस्पिटल- लिवर, किडनी, ब्लड शुगर, हार्ट, प्रोटीन से संबंधित समस्त प्रकार के जांच होने वाले मशीन को चलाने वाले हड़ताल पर है। पहले एक दिन में 500 प्रकार के जांच किया जाता था आज 150 नही पहुंच पा रहा है।

नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी नहीं खुल रहे स्कूल, शिक्षक गायब

कांकेर। शिक्षा सत्र शुरू होते ही अंदरूनी गांवों में शिक्षा की समस्या उजागर होने लगी है। इसी को लेकर कोयलीबेड़ा ब्लॉक के छोटेबेठिया में स्कूली बच्चे और ग्रामीणों ने बेचाघाट से छोटेबेठिया तक रैली निकाल प्रदर्शन किया। रैली में जिले के छोटेबेठिया इलाके और नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि 26 जून से शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन अब तक कई स्कूलों का गेट भी नहीं खुला है। शिक्षक नहीं आने के चलते बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे वे मुख्यधारा से भटक सकते हैं। ग्राम पंचायत कोंगे के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सभी स्कूलों के शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं। कई बार सरपंच, सचिव, संकुल समन्वयक और बीईओ को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं, स्कूल भवन भी जर्जर स्थिति में हैं। हालत यह है कि गांव के गोटूल में ही स्कूल संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा ओरछा ब्लॉक के बिनागुंडा, कोंगे और कोयली बेड़ा ब्लॉक के बंगोघोड़िया स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नए सत्र में अब तक शिक्षक उपस्थित नहीं हुए हैं। अव्यवस्था के लिए विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है।

कलेक्टर ने राजनैतिक दलों से जल्द से जल्द बूथ एजेंटों की मांगी सूची

जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में लिया गया। कलेक्टर ने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले सहमति और सुझावों के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होने कहा कि राजनीतिक दल बूथ लेबल एजेन्टों की सूची जल्द से जल्द दें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जुलाई तक डोर टू डोर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सत्यापन, 02 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, दावा-प्रस्ताव 31 अगस्त तक, 12,13,19 और 20 अगस्त को विशेष जागरूकता शिविर और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा के सम्बंध में जानकारी दी गई।

कलेक्टर ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से विधानसभावार बीएलओ स्तर पर मतदाता फार्म भरने की प्रगति की समीक्षा की और 10 जुलाई तक फार्म भरने की कार्यवाही शत-प्रतिशत करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फार्म में नए मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए, विशेष कर नगरीय निकाय क्षेत्र के युवाओं को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में निर्वाचन मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जाना है, साथ ही दावा-आपत्ति को लिखित में लेते हुए लिखित जवाब भी दिया जाना चाहिए।

इस दौरान उप निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नंद कुमार चौबे, ओम प्रकाश वर्मा, ऋ्रषु राज बिसेन, राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप, जनता कांग्रेस के प्रतिनिधि और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सहकारी समिति के गोदाम से 75 बोरी खाद की हुई चोरी

जगदलपुर। सहकारी समिति जगदलपुर में बीती रात चोरों ने शटर को तोड़कर गोदाम में रखे 75 बोरी खाद की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा की गई है। चोर समिति में लगाए गए कैमरे एवं डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। सहकारी समिति के प्रबंधक सोनू राव ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई है। जगदलपुर सहकारी समिति से करीब 500 से अधिक किसानों को खाद और बीज का वितरण किया जाता है। प्रबंधक का कहना है कि समिति से खाद के चोरी होने के बाद किसानों को खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों से बात की जाएगी। खाद लेने पहुंचे किसानों ने कहा कि गोदाम में खाद की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। किसानों ने बताया कि सुरक्षा को लेकर की गई लापरवाही का चोरों ने फायदा उठाया। गोदाम का शटर काफी कमजोर था। प्रबंधक ने कहा कि खाद की सुरक्षा को लेकर केवल सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी, यहां पर चौकीदार की तैनाती नहीं की गई है।

कोरबा जिले में पीपीटी की प्रवेश परीक्षा 9 को

कोरबा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले पीपीटी प्रवेश परीक्षा जिले में 09 जुलाई 2023 को पूर्वान्ह 09 बजे से 12.15 बजे तक आयोजित किया जायेगा। जिले में पीपीटी की परीक्षा हेतु 04 केन्द्र बनाया गया है। जिसमें कुल 1295 परीक्षार्थी शामिल होंगें। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु शासकीय ईव्हीपीजी महाविद्यालय रजगामार रोड कोरबा को मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07759-221458 है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के दिशा-निर्देश में परीक्षा के सुचारू संपादन व जिला कोषालय कोरबा से परीक्षा केन्द्र के लिए गोपनीय सामग्री प्राप्त करने व परीक्षा समाप्ति पश्चात उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री अपने निगरानी में सील्ड कराकर समन्वयक केंद्र में जमा करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को प्रशासनिक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसके अंतर्गत परीक्षा केंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झगरहा हेतु सहायक अभियंता क्रेडा एन. के. रॉय को प्रशासनिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

रीपा के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : जिपं सीईओ

सूरजपुर। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री लीना कोसम ने जिला पंचायत सभाकक्ष में जनपद सीईओ तथा आरईएस विभाग के एसडीओ की समीक्षा बैठक ली। जिला पंचायत सीईओ ने गौठानों में अधूरे कार्य को पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन गौठान में फेसिंग के कार्य पूर्ण नहीं हुए उन्हें तत्काल पूर्ण कराये। रीपा मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। रीपा के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी। गौठानों में रीपा के जितने वर्किंग शेड बन रहे हैं वे गुणवत्तापूर्ण बने। अभी बरसात का समय है इसलिए किसी रीपा केंद्र के वर्किंग शेड में पानी की सिपेज की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने वृन्दावन एवं चंदननगर के गौठानों के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। जिले का हर रीपा केन्द्र साफ-सुथरा और स्वच्छ दिखना चाहिए। यह समस्त जनपद सीईओ की जिम्मेदारी है। उन्होंने जनपदों में जितने भी मिट्टी के कार्य अधूरे उनका जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।

मूलभूत समस्याओं को लेकर मंडावी ने पीएम को लिखा पत्र

नगरी। सांसद मोहन मंडावी के विगत दिनों सांकरा प्रवास के दौरान सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रिसगांव,करही, खल्लारी, फरसगांव सहित अन्य 25 ग्राम के अभ्यारण संघर्ष समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर सांसद मोहन मंडावी से अभ्यारण क्षेत्र के विकास को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था।जिस पर सांसद मोहन मंडावी जी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नगरी विकासखंड के अभ्यारण क्षेत्र के ग्रामों में आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज तक मूलभूत सुविधा सड़क बिजली पानी एवं शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है। सांसद मोहन मंडावी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर अभ्यारण क्षेत्र के लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए मांग की है कि अरसीकन्हार से जोरातराई, गहनासियार से चमेंदा तक,खल्लारी से रिसगांव तक,ठोठाझरिया से बिरनासिल्ली तक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण किया जावे।

आयुष्मान कार्ड बनाने महाअभियान 7 को

कोरबा। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयुष्मान कार्ड पंजीयन महाअभियान 07 जुलाई 2023 को जिले के सभी नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। महाभियान में जिले के सभी शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम व ग्राम पंचायतों में, जिले के सभी स्कूलों सहित सभी च्वाईस सेंटरों में प्रात: 08 बजे से सायं 06 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अभियान की सफ्लता के लिए 03 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है। आयुष्मान कार्ड के लिए राशन कार्डधारी सभी परिवार पात्र होगें। महाअभियान में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड जारी करने के उद्देश्य से हितग्राहियों को शिविर स्थल में राशन कार्ड एवं आधार कार्ड, आधार से लिंक वाली मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार महाअभियान शिविर में शिविर स्थल पर हितग्राहियों को लाने के लिये क्षेत्र के मितानिन को जिम्मेदारी दी गई हैं।

प्रदेश में हाथियों का आतंक जारी, जशपुर में हाथी का हमला

जशपुर। छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को एलिफेंट अटैक में एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना की पुष्टि वन विभाग के अधिकारी ने की है। बुजुर्ग सुभाष यादव गांव के पास ही वन उपज इक्टठा करने गए थे। तभी हाथी अचानक वहां आ धमका। उसने बुजुर्ग को कुचल दिया। हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई।

हाथी के हमले से लोगों में दहशत

हाथियों के उत्पात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। जशपुर का यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। हाथी के हमले की सूचना लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एलिफेंट अटैक में मौत की पुष्टि की है। हाथी के हमले में मौत के बाद इलाके में गम और मातम का माहौल है।

वन विभाग ने कहा यह घटना तब हुई, जब सुभाष यादव बादलखोल अभयारण्य वन क्षेत्र नारायणपुर पोखरटोली गांव के पास गया हुआ था। वह यहां वन उपज को जुटाने का काम कर रहा था। जब काफी देर बाद सुभाष यादव घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। जब परिवार वाले पोखरटोली गांव के पास थेंगना कूचा जंगल में पहुंचे तो देखा की सुभाष यादव का शव कुचला हुआ है। मृतक को हाथियों के दल के घूमने की जानकारी थी। फिर भी वह इलाके में पहुंच गया।

पुलिस और वनकर्मियों ने घटना की जांच शुरू की

पुलिसकर्मियों और वन कर्मियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को 25 हजार रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है। बाकी का 5।75 लाख रुपये का मुआवजा बाद में दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में हाथियों से खतरा ज्यादा

छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में हाथियों से ज्यादा खतरा है। यहां मानव हाथी संघर्ष बीते एक दशक से चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा हाथियों के हमले की घटनाएं जशपुर, रायगढ़,कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर में देखने को मिलते हैं। वन विभाग के अनुसार बीते तीन साल में छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में 230 से भी अधिक लोग मारे गए हैं।

4387 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को मिला अंत्योदय राशन कार्ड

जशपुर। जिला प्रशासन द्वारा जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों का प्राथमिकता से अंत्योदय राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अब तक लगभग 4387 परिवारों को राशन कार्ड बना कर दिया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों के पहाड़ी कोरवा परिवारों को उनके नजदीक के उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह समय पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूची अनुसार जिले के विभिन्न ग्रामों में निवासरत् दिव्यांगजनों का खाद्य विभाग द्वारा पात्रतानुसार निश्क्तजन एवं अंत्योदय राशन कार्ड जारी किया गया है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन दिव्यांगजनों का नाम, उनके परिवार के राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है उनका पृथक से राशन कार्ड जारी किया जा रहा है। ऐसे प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी जिनके मुख्या दिव्यांग है उनको अंत्योदय राशन कार्ड जारी किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में सामान्य राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड और दिव्यांगजनों को शत् प्रतिशत राशन कार्ड जारी किया गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् 1 सदस्यीय प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी को 10 किलो चावल प्रति माह, 2 सदस्यीय प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी को 20 किलो प्रति माह, 3 से 5 सदस्यीय राशनकार्ड धारी को 35 किलो प्रति माह तथा 5 से अधिक सदस्यीय वाले प्राथमिकता राशन कार्डधारी को 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह राशन दिया जा रहा है। इसी प्रकार अन्त्योदय राशन कार्डधारी को 35 किलो चावल प्रति माह दी जा रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करने आह्वान किया

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध नेताओं का आह्वान किया कि वे मिलजुलकर पार्टी के लिए काम करें और आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। वह कांग्रेस के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभागों की ओर से आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। खरगे ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के नेताओं को खुद को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गयी थी। इस मिशन का मकसद एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं को तराशना और निखारना है जिससे वे अपने समुदायों में पार्टी के आधार को और विस्तार दें।

यूसीसी के नाम पर विवादों का पिटारा न खोला जाए : मोइली

नयी दिल्ली। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर छिड़ी बहस के बीच पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विधि आयोग एवं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया कि वे पर्सनल लॉ पर विवादों का पिटारा न खोलें तथा समाज में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा न करें। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यह मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि समाज में विभाजन पैदा किया जा सके, देश को अस्थिर किया जा सके और भारतीय समाज की विविधिता को खत्म किया जा सके। मोइली ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से समान नागरिक संहिता की बात की। संविधान में इसका उल्लेख है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में यह फैसला किया था कि समान नागरिक संहिता को अनिवार्य नहीं बनाया जाए क्योंकि यह भारतीय समाज की विविधता से संबंधित है।'

तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट पर भड़के लालू यादव

पटना। बिहार की राजधानी पटना में राजद पार्टी का 27 वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया। इस मौके पर लालू यादव राज्य के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर केंद्र सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभी जो करना है कर लें। लेकिन जब सरकार जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। अभी जिसके मन में जो आता है, वो करें। मुकदमा करना है तो वो भी करें। लेकिन, जिस दिन आप जाइएगा उस दिन क्या होगा। हमलोग अब डरने वाले नहीं है। इस बार कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू यादव ने आगे कहा है कि हमने एकता को लेकर पटना में बैठक बुलाया था। हम लोग एकजुट हैं। राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि हर चुनाव में आरजेडी ने कीर्तिमान स्थापित किया।

कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सबूत मेरी जेब में है : कुमारस्वामी

बेंगलुरु। कांग्रेस के ताज वेस्ट एंड को लेकर पूर्व सीएम कुमारस्वामी पर सवाल उठाने के बाद अब जेडीएस नेता ने पलटवार किया है। कुमारस्वामी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सबूत उनकी जेब में हैं। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोलते समय एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा कि मैं (सबूत) अपनी जेब में रखता हूं। पत्रकारों से बात करते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मैं किसी भी समय इसे जारी कर सकता हूं, आप चिंता क्यों करते हैं? बिना किसी उचित जानकारी के मैं कुछ भी जारी नहीं करूंगा। कैसे एक जिम्मेदार मंत्री अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए पैसा इकट्ठा किया-सब कुछ यहाँ है। अपने ऊपर कांग्रेस पार्टी के ताज वेस्ट एंड ट्वीट पर जवाब देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि मैं उन लोगों से स्पष्टीकरण लेना चाहता था जिन्होंने मेरे वेस्ट एंड में रहने के मुद्दे पर ट्वीट किया था कि क्या उन्हें भुगतान करने के लिए कोई बिल मिला है...वे अपना सिर क्यों खुजला रहे हैं।

एनसीपी के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट में नाराजगी

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में अजित पवार के शामिल होने के बाद से शिवसेना-भाजपा खेमे में सबकुछ ठीक नहीं है। खबरों की मानें तो विभागों के बंटवारे को लेकर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इन खबरों के बाद कि शिवसेना-बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाले एनसीपी नेताओं को मलाईदार विभाग मिल सकते हैं, सीएम खेमे के विधायकों ने बगावत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि वित्त, जल संसाधन और लोक निर्माण मंत्रालय एनसीपी को नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल, शिंदे गुट के विधायकों को डर है कि अगर अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया तो वे विकास फंड देने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान वे विधायक हैं जो सेना-बीजेपी कैबिनेट में मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे। संजय शिरसाट ने कहा कि अजित पवार समूह के सरकार में शामिल होने के बाद, उनके समूह के कुछ लोग नाराज़ थे ।

अजित पवार बने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद पवार को पद से हटाया

मुंबई। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। बुधवार को महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक अजित पवार अब खुद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अजित गुट ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजित गुट ने चुनाव आयोग के पास याचिका भी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल ने 30 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। यह दावा अजित पवार गुट की ओर से किया गया है।

दरअसल, बुधवार को दोनों गुटों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई। एक ओर अजित पवार ने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे। वहीं, शरद पवार के साथ लगभग 14 से 15 विधायक खड़े हुए। कुछ विधायकों ने दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी उनके (शरद पवार) लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। शरद पवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में भी भाजपा नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं... इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है... आप (शरद पवार) हमें अपना आशीर्वाद दें... लेकिन आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं?.. हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उनकी अब तक की राजनीतिक उपलब्धियां पार्टी प्रमुख और उनके चाचा शरद पवार के कारण हैं। अजित पवार ने कहा, मैं जो कुछ भी हूं, शरद पवार की वजह से हूं।

अजित पवार ने कहा कि आपने इस्तीफे की बात की, फिर अध्यक्ष के लिए कमेटी बनाई। सुप्रिय सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। फिर आपने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। क्या आज हमें सरकार चलाने की ताकत नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले इस्तीफा दिया, फिर वापस लिया। अजित पवार ने कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री

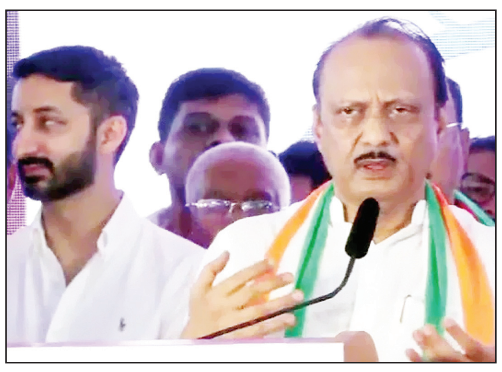

पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होता। उन्होंने कहा कि 2017 में भी हमारी वर्षा बंगले पर मीटिंग हुई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं छगन भुजबल, जयंत पाटिल के आदेश पर मैं और कई अन्य लोग वहां गये थे। वहां बीजेपी के कई नेता भी थे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और संरक्षक मंत्रियों के पदों पर चर्चा हुई। लेकिन बाद में हमारी पार्टी पीछे हट गयी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम करने के लिए पद चाहिए।

अजित पवार गुट ने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर किया दावा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में अजित पवार और शरद पवार के बीच अंदरूनी कलह बुधवार को चुनाव आयोग तक पहुंच गई, जहां अजित गुट ने एनसीपी और उसके पार्टी चिन्ह पर दावा किया। कथित तौर पर, अजित पवार के समूह ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों के 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किए हैं। खबर के मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पार्टी चिह्न पर दावा करने वाली याचिका मिली है। शरद पवार गुट की ओर से भी आयोग को जयंत पाटिल से एक चेतावनी मिली है कि उन्होंने 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष एक कैविएट दायर कर आग्रह किया है कि गुटीय लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए।

जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो भाजपा का क्यों नहीं : प्रफुल्ल पटेल

प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को अपने और अन्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेताओं के एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने के फैसले का बचाव किया। एमईटी बांद्रा में बैठक के दौरान विधायकों को संबोधित करते हुए पटेल ने महा विकास अघाड़ी गठबंधन बनाने के लिए राकांपा से शिवसेना को समर्थन देने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है? हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं।

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में भाजपा के साथ चले गए और वे अब संयुक्त विपक्ष का हिस्सा हैं। हाल ही में पटना में हुई विपक्ष की बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैं शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था और वहां का दृश्य देखकर मुझे हंसने का मन हुआ। वहां 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 ने लोकसभा में केवल 1 सांसद है और एक पार्टी ऐसी है जिसके 0 सांसद हैं। उनका दावा है कि वे बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला (एनडीए में शामिल होने का) लिया है वह देश और हमारी पार्टी के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं।

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब महाराष्ट्र में एमवीए सरकार गिरने वाली थी, तब सभी राकांपा विधायकों एवं मंत्रियों ने शरद पवार से भाजपा के साथ जाने का अनुरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि अजित पवार द्वारा मुंबई में बुलाई गई राकांपा की बैठक में पार्टी के 35 विधायक, पांच विधान पार्षद शामिल हुए। अजित पवार ने इस बैठक में कहा कि राकांपा ने कांग्रेस से अधिक विधायक होने के बावजूद 2004 में मुख्यमंत्री पद हासिल करने का अवसर खो दिया। 83 वर्षीय शरद पवार पर चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 2014 में नरेन्द्र मोदी के करिश्मे की वजह से ही सत्ता में आयी।

उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वह दोहराया गया

हमें सत्ता की भूख नहीं, लोगों के लिए काम करते रहेंगे : शरद पवार

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। एक ओर अजित पवार गुट है तो दूसरी ओर एनसीपी संस्थापक शरद पवार हैं। बुधवार को दोनों गुटों की ओर से विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। शरद पवार ने अपने गुट के विधायकों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ, वहीं एनसीपी के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि अजित पवार को मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर सहमत नहीं थे तो बातचीत से हल निकाला जा सकता था। गलती को सुधारना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने गलत काम किया है तो आप सजा के लिए तैयार रहें।

शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने एक भोपाल की रैली में एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अगर एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है तो सरकार में क्यों शामिल किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने (बीजेपी) एनसीपी को भ्रष्ट कहा। तो, अब आपने राकांपा के साथ गठबंधन क्यों किया है?...उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वह दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार को कोई समस्या थी तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उसके मन में कुछ था तो वह मुझसे संपर्क कर सकता था। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता की भूख नहीं है; हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो विचारधारा ठीक नहीं, उसके साथ क्यों बैठना?

मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि आज पूरा देश हम पर नजर रख रहा है...एनसीपी के लिए यह बैठक ऐतिहासिक है। हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना होगा। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने अलग होने

का फैसला किया, उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजित पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिह्न हमारे पास है, वह कहीं नहीं जायेगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाए, वे हमारे साथ हैं। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता (शरद पवार) का नहीं। यह लड़ाई भाजपा की सरकार के खिलाफ़ है। भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है।

असली राकांपा शरद पवार के साथ है और असली चुनाव चिन्ह हम हैं : सुप्रिया सुले

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने मुंबई में बुधवार को कहा कि असली राकांपा शरद पवार के साथ है और असली चुनाव चिन्ह हम हैं। सुले ने कहा, हमारा अनादर करें, लेकिन हमारे पिता (शरद पवार) का नहीं। यह लड़ाई भाजपा सरकार के खिलाफ है। भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है।

खेल

प्रमुख समाचार

जिंबाब्वे विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से बाहर

नईदिल्ली। स्कॉटलैंड की जीत और मेजबान जिंबाब्वे का सपना चकनाचूर हो गया। स्कॉटलैंड ने न केवल जिम्बाब्वे को हराया बल्कि विश्व कप में स्थान की दौड़ से भी बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड के पास अब भारत में विश्व कप खेलने का मौका है। श्रीलंका की टीम पहले ही क्वालीफाई कर ली है।

जिम्बाब्वे को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। जिम्बाब्वे खिलाड़ी सिकंदर रजा बाहर होने के बाद आंसू नहीं रोक सके। फूट-फूट कर रोने लगे। कई फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कई ने कहा कि आगे के बारे में सोचिए। रजा ने 40 गेंद में 34 रन बनाया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। माइकल लीस्क के आलराउंड प्रदर्शन और क्रिस सोल की शानदार गेंदबाजी से स्कॉटलैंड ने विश्व कप क्वालीफायर्स के सुपर सिक्स के मैच में मेजबान जिंबाब्वे को 31 रन से हराकर भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली प्रतियोगिता में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को पंख लगाए।

जिंबाब्वे इस मैच में हार से विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से लगभग बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड के अब छह अंक हो गए हैं और वह श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिंबाब्वे के भी छह अंक हैं लेकिन उसने अपने सभी मैच खेल लिए हैं और उसका नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है। स्कॉटलैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 234 रन बनाए। उसकी तरफ से लीस्क ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। उनके अलावा मैथ्यू क्रॉस ने 38, ब्रैंडन मैकमुलेन ने 34 और जॉर्ज मुंसे ने 31 रन का योगदान दिया। जिंबाब्वे के लिए सीन विलियम्स ने तीन विकेट लिए। जिंबाब्वे के लिए यह अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य भी पहाड़ जैसा बन गया और उसकी टीम रेयान बर्ल की 83 रन की पारी के बावजूद 41.1 ओवर में 203 रन पर सिमट गयी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 33 अंक टूटा निफ्टी 19,400 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में पिछले पांच सत्रों से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया। आज के कारोबार में बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 33 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में 27 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 19,415.85 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.7 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की गई। स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले, पर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी (प्रत्येक में 3 फीसदी नीचे), आयशर मोटर्स (2.7 फीसदी), टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, विप्रो और एक्सिस बैंक में मुनाफावसूली का सिलसिला चलने से बाद बाजार नुकसान में आ गए।

तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंचा पीएमआई

नईदिल्ली। महंगाई के कारण भारत के सर्विस सेक्टर में व्यावसायिक गतिविधि की वृद्धि जून के महीने में तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई, जबकि आउटपुट शुल्क में लगभग छह वर्षों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। बुधवार को एक निजी सर्वे में इसकी जानकारी दी गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वेक्षण में सर्विस सेक्टर का पीएमआई मई के 61.2 से घटकर जून में 58.5 हो गया। अप्रैल के बाद यह सबसे निचला स्तर है। अप्रैल में यह 62 था। मंगलवार के आंकड़ों से पता चला कि भारत का विनिर्माण पीएमआई मई में 57.8 से गिरकर जून में 58.7 पर आ गया। परिणामस्वरूप, भारत की समग्र पीएमआई रीडिंग मई में 61.6 से घटकर जून में 59.4 पर आ गई। सेवा प्रदाताओं ने पहली वित्तीय तिमाही के अंत में नए व्यवसाय के प्रवेश में तेज विस्तार देखा।

पेटीएम का जीएमवी जून तिमाही में 37 फीसदी बढ़ा

नईदिल्ली। पेटीएम ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) में अप्रैल-जून की तिमाही में 37 फीसदी की वृद्धि हुई है और यह 4.05 लाख करोड़ रहा है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जीएमवी से आशय पेटीएम के मंच के जरिये दुकानदारों को अदा किए जाने वाले कुल भुगतान से है। इससे पिछले साल की जून तिमाही में पेटीएम का जीएमवी 2.96 लाख करोड़ रुपये था। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा, 'जून तिमाही में जीएमवी 4.05 लाख करोड़ रुपये (49.3 अरब डॉलर) रहा, जो सालाना आधार पर 37 फीसदी की वृद्धि है।' तिमाही के दौरान पेटीएम का ऋण वितरण ढाई गुना होकर 14,845 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 5,554 करोड़ रुपये था। इस दौरान पेटीएम द्वारा दिए गए ऋणों की संख्या 51 फीसदी बढ़कर 85 लाख से 1.28 करोड़ हो गई।

भारतीय निर्यातकों के लिए जीएसपी लाभ की बहाली आज समय की जरूरत

नईदिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ की निर्यात-आयात (एक्जिम) पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा है कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिका द्वारा वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) लाभ की बहाली के लिए शीघ्र समाधान आज समय की जरूरत है, क्योंकि इससे द्विपक्षीय व्यापार को और तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और अमेरिका घरेलू निर्यातकों के लिए वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली लाभ की बहाली की मांग पर चर्चा करने को सहमत हो गए हैं। इससे घरेलू निर्यातकों को फायदा होगा। अमेरिका में पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2019 में भारत के लिए जीएसपी को रद्द कर दिया था। जीएसपी पात्र विकासशील देशों को अमेरिका को शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देता है।

बढ़ते कर्ज के साथ ब्याज लागत से जूझतीं अर्थव्यवस्थाएं

शंकर अय्यर

पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के प्रमुखों ने पुर्तगाल के सिंट्रा में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) के मंच पर बैठक की। इस बैठक का कटु संदेश यह है कि - मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहेगी, जिससे विकास और नौकरियों पर असर पड़ेगा, ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होगी तथा मंदी को टाला नहीं जा सकता। इस संदेश ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में गूंजने वाली चेतावनीपूर्ण सलाह और भय को और बढ़ा दिया है। मगर सट्टेबाजों और शेयर बाजार के तेजड़ियों के लिए ये चेतावनियां बेकार हैं। भारत में बीएसई सूचकांक व निफ्टी-50 नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इस उछाल का मुख्य कारण एक वैश्विक बैंकिंग दिग्गज का उदय है। मूल कंपनी एचडीएफसी के साथ विलय के बाद एचडीएफसी बैंक का मूल्य करीब 172 अरब डॉलर हो गया है, जो जेपी मार्गन, बैंक ऑफ अमेरिका एवं आईसीबीसी के बाद दुनिया का चौथा बड़ा बैंक बन गया है।

यकीनन भारत में शेयरों में बढ़ोतरी उचित है-यह सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और मार्च के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 10 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। तथ्य यह है कि सुर्खियों के बावजूद इस वर्ष जनवरी से सेंसेक्स और निफ्टी-50 में करीब सात फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, यूरोप और अमेरिका में सूचकांक?(जहां मंदी आने का अनुमान है) एस ऐंड पी-500 15 फीसदी ऊपर है, 1983 के बाद से नैस्डेक के लिए पहले छह महीने सबसे अच्छे रहे हैं और 32 प्रतिशत ऊपर है तथा यूरो शेयर 15 फीसदी ऊपर है। इस आश्वस्ति का मतलब क्या है? सबकी निगाहें तकनीकी शेयरों पर

हैं, लेकिन अमेरिका में 2022 में तकनीकी क्षेत्र में गिरावट आई, जिसके चलते नौकरियां चली गईं और नैस्डेक 33 फीसदी से अधिक लुढ़क गया। इसके अलावा, 2023 में अमेरिका में तकनीकी शेयरों में उछाल चैटजीपीटी द्वारा जेनरेटिव एआई की लोकप्रियता के कारण है। इसकी तुलना में यूरोप के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और न ही उसके पास एआई का आभामंडल है। चीन के साथ व्यापार पर निर्भर जर्मनी और फ्रांस के शेयर चीन में खराब रिकवरी के बावजूद उछाल पर हैं।

अप्रैल, 2022 से केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। इन बढ़ोतरी के बावजूद मुद्रास्फीति स्थिर है और केंद्रीय बैंकों ने चेतावनी दी है कि उच्च दरें लंबे समय तक बनी रहेंगी। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब उच्च लागत, कम विकास और नौकरियों का नुकसान है। लेकिन शेयर बाजार इससे सहमत नहीं है।

केंद्रीय बैंकों की निराशा और शेयर बाजार की आशा का सह-अस्तित्व नीति-निर्माताओं के लिए हैरान करने वाला विरोधाभास है। जनवरी, 2022 से अमेरिका में उपभोक्ताओं का भरोसा उच्च स्तर पर है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का अनुमान है कि अमेरिकी कंपनियों के पास 20 खरब डॉलर से अधिक नकदी है। अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में उछाल पहली तिमाही के 1.3 से दो प्रतिशत में संशोधन से परिलक्षित होता है। यह व्यवस्था के जरिये बाजार में डाले गए धन के स्तर को देखते हुए दरों में बढ़ोतरी की प्रभावकारिता पर सवाल उठाता है।

वास्तविक असुविधाजनक सच्चाई यह है कि राजनीति से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे लगातार मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं-ब्रिटेन में ब्रेग्जिट, उम्रदराज कार्यबल और अमेरिका व यूरोप में जनसांख्यिकीय बदलाव, वस्तुओं एवं ऊर्जा की भू-राजनीति तथा विकासशील देशों से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों के प्रवास के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया। संदर्भों को देखते हुए यह पूछना जरूरी है कि क्या दो फीसदी का मुद्रास्फीति लक्ष्य ईमानदार और यथार्थवादी है। ऊंची दरों के बने रहने के दावे वैश्विक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का संकेत देते हैं-खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते कर्ज और ब्याज लागत से जूझ रही हैं। अब वक्त आ गया है कि इस पर ईमानदार बहस हो।

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से तय होगा माकपा का भविष्य

जितेंद्र कुमार सिंह

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होना है और उसके परिणाम 15 जुलाई को आ जाएंगे। यही तय करेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन का कितना हिस्सा वापस करने में कामयाबी मिली है। क्योंकि 2021 के विधानसभा के चुनाव के बाद से माकपा की ताकत दिन-ब-दिन कमजोर होती गई है। मौजूदा विधानसभा में माकपा का एक भी विधायक नहीं है। पश्चिम बंगाल से माकपा का कोई सांसद भी नहीं है। इन दो वर्षों में तस्वीर कुछ बदली है। दरअसल उम्मीद की किरण इसलिए दिख रही है क्योंकि इस बार के पंचायत चुनाव में माकपा के करीब 49 हजार और सहयोगी कांग्रेस के 18 हजार उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद है। जबकि भाजपा के 57 हजार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले पंचायत चुनाव के मुकाबले सिर्फ उम्मीदवार ही उल्लेखनीय नहीं है बल्कि पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि माकपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तृणमूल समर्थकों की हिंसा का मुकाबला कर रहे हैं। जब उन्हें पुलिस वाले परेशान करते हैं तो वे थाने के सामने जमा होकर प्रतिवाद करते हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक हुई चुनावी हिंसा में करीब 15 लोग मारे जा चुके हैं फिर भी विपक्ष मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं थी। भाजपा सहित पूरे विपक्ष ने कमोबेश सरेंडर कर दिया था। पिछले पंचायत चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जिला परिषद की कुल 825 सीटों में से माकपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस को छह सीटें मिली थी। पंचायत समिति की नौ हजार से भी अधिक सीटों में से माकपा को कुल 111 सीटें मिली थी। इस बार बदलाव आने की उम्मीद बनी है। इसकी वजह यह है कि माकपा की शक्ति तो भाजपा के अंदर निहित है और अब इसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो तृणमूल कांग्रेस के सरकार की दमन से त्रस्त माकपा और कांग्रेस के समर्थक भाजपा की शरण में चले गए थे। इसलिए बंगाल में यह मुहावरा काफी प्रचलित हुआ था कि पहले राम फिर वाम। अब राम से वाम की तरफ जाने की राह खुल गई है। अगर 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर एक नजर डालें तो राम-वाम की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करीब 11 फीसदी, माकपा को 20 फीसदी और कांग्रेस को 12 फीसदी वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में स्थिति पूरी तरह बदल गई। भाजपा को 38 प्रतिशत वोट मिला था। माकपा को पांच प्रतिशत और कांग्रेस को तीन प्रतिशत वोट मिले थे। यानी माकपा और कांग्रेस ने 24 फीसदी गवाया था तो भाजपा के वोट में 27 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई थी। अब इन समर्थकों की वापसी का कयास दो कारणों से लगाए जा रहे हैं। पहला तो यह है कि विपक्ष इस बार काफी मजबूत स्थिति में है। दूसरी वजह तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में एक मंत्री, कई विधायक, तृणमूल कांग्रेस के नेता और शिक्षा विभाग के अफसर इन दिनों विभिन्न जेलों में बंद है। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण राज्य सरकार को मनरेगा के तहत दिया जाने वाला फंड बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीएजी को सौंपी है। इस वजह से लोगों को सौ दिन की रोजगार योजना के तहत रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास आवास योजना में भी घोटाले के आरोप लगे हैं। पंचायत चुनाव में इन मुद्दों का खासा असर पड़ सकता है। इस वजह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है और विपक्ष के हमले की धार तेज हो गई है। माकपा की राज्य कमेटी के सचिव मोहम्मद सलीम कहते हैं कि इस बार के चुनावी मुकाबले में जो संकेत मिल रहे हैं वह पिछले चुनाव में नहीं दिखे थे। इस पंचायत चुनाव का एक और पहलू है जो अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पंचायत सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए माकपा, भाजपा और कांग्रेस एक ही कतार में नजर आ रही हैं।

अजित पवार एपिसोड के 'मान्य' सूत्र

अजय बोकिल

देश के सबसे धनी राज्य माने जाने वाले महाराष्ट्र में सत्ता के लिए खेले गए पार्ट थ्री एपिसोड का अंत क्या होगा? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह सियासी धारावाहिक अभी चल ही रहा है। इस देश में काका के खिलाफ भतीजे की राजनीतिक बगावत नई बात नहीं है। लेकिन नई बात अगर कुछ है तो ये कि इस देश में आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार अब कोई मुददा नहीं है और यह भी कि अब भारतीय राजनीति में 'थूक कर चाटना' भी सर्वमान्य कल्चर बन चुका है। सत्ता स्वार्थ के लिए कभी भी यू-टर्न ले लेना अब राजनीतिक राजमार्ग पर चलने का अलिखित ट्रैफिक नियम बन गया है और कुछेक को छोड़ कोई भी इसका अपवाद नहीं है। महाराष्ट्र का ताजा राजनीतिक घटनाक्रम इसका बड़ा उदाहरण है। कल को यही बिहार में भी दोहराया जा सकता है। इस खेल में अगर कोई मूर्ख बन रही है तो वो है जनता, जिसके पास निरीह विवशता के अलावा और कोई विकल्प शायद विकल्प नहीं छोड़ा गया है।

भारतीय समाज में भ्रष्टाचार शब्द अब एक सियासी फुटबॉल की तरह है, जिसे हर कोई अपनी सुविधा और मकसद से किक मारता रहता है। कभी-कभी यह सेल्फ गोल में भी बदल जाती है। इस खेल का अजब नियम यह है कि भ्रष्टाचार की यह बॉल जब तक दूसरे के पाले में होती है, तब तक 'भ्रष्टाचार' होती है और जब वह अपनी 'डी' में होती है तो शिष्टाचार का रूप ले लेती है। यहां तक कि उसका रंग और राजनीतिक तासीर तक बदल जाती है।

क्या बोले शरद पवार?

गौर करें कि बरसों से काका शरद पवार के राजनीतिक पोषण आहार पर पले भतीजे अजित पवार के भाजपा शिवसेना महायुति के साथ सत्ता में जाने के फैसले से दुखी राकांपा अध्यक्ष (कम से कम अभी तक तो हैं हीं) शरद पवार ने कहा कि मेरे जिन लोगों पर भाजपा ने बरसों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो अब भाजपा के साथ मिलते ही 'दोषमुक्त' हो गए हैं। उनका कहने का आशय यह था कि भाजपा अब एक 'राजनीतिक गंगा' है, जिसमें स्नान करते ही स्वतः पाप प्रक्षालन हो जाता है। इस हिसाब से उस अजित पवार एंड कंपनी, जिसके पीछे ईडी लगी है, भाजपा के हमकदम होते ही ईमानदारी का बाना धारण कर चुकी है। ये वही कंपनी है, जिसके खिलाफ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भ्रष्टाचार के खुले आम आरोप लगाया करते थे। लेकिन अब भाजपा के 'सुरक्षा चक्र 'में आते ही इन सभी कथित भ्रष्टाचारियों ने राहत की गहरी सांस ले ली है।

जो कल तक थे अपने, आज वो भ्रष्टाचारी

एक दिलचस्प बात और कि जो शरद पवार 'अजित एंड कंपनी' को अब परोक्ष रूप से 'भ्रष्टाचारी' बता रहे हैं, वो कल तक इन सबको अपने परिवार का ही हिस्सा मानते रहे हैं। यानी उनकी छत्रछाया में चलने वाला भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं था, 'परफॉर्मेंस' था। (कुछ लोगों का तो अभी भी मानना है कि यह सब काका भतीजे का मिला जुला गेम है) राजनीतिक छत्र बदलते ही वह फिर भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया है।

इसका अर्थ यही है कि अपने भ्रष्टाचार करें तो वह भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। यह शब्द और भाव केवल 'गैरों' के लिए है। हालांकि, खुद काका शरद पवार पर भी उनके केन्द्रीय कृषि मंत्री रहते कदाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन कभी किसी ने उसकी जांच इसलिए नहीं कराई, क्योंकि विरोध के झीने पर्दे में शरद पवार निजी रिश्तों का सौजन्य कायम रखते आए हैं।

साथ ही राजनीति में उनका सत्ता के अलावा कभी कोई वैचारिक आग्रह नहीं रहा। इस हिसाब से अजित पवार उसी 'शरदवाद' को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आज शरद पवार अपने सियासी गणित के हिसाब से विपक्ष की राजनीति कर भले कर रहे हों, लेकिन सियासी अक्षत वर्षा करने वाले हर दल में हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हैं, जो उन्हें 'शरदराव' कहते आए हैं। उनकी पार्टी भाजपा तो काफी पहले से विरोधियो के राजनीतिक पिंडदान के लिए राकांपा के 'काकस्पर्श' की आस लगाए बैठी थी।

क्या है 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स'?

वैसे इस देश में निर्वाचित सरकार को गिराने की 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' के आदि आख्यान की रचयिता भी कांग्रेस ही है, जिसने सबसे पहले 1995 में भाजपा की केशुभाई पटेल की निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए भाजपा नेता शंकरसिंह वाघेला के नेतृत्व में बगावत कराई और मप्र के खजुराहो के होटल में बागी विधायकों को रूकवाया। हालांकि, बाद में कांग्रेस के समर्थन से बनी वाघेला की सरकार भी गिर गई और उसी के साथ गुजरात में कांग्रेस स्थायी विपक्ष की भूमिका में चली गई।

अब मोदी-शाह के जमाने में भाजपा ने इस खेल में कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया और इस खेल के अहम कारकों में 'धन की देवी' भी जुड़ गई। इससे यह सूत्र भी स्थापित हुआ कि राजनीति में भ्रष्टाचार एवं कथनी और करनी के भेद का महत्व शून्य है। इसकी व्याख्या अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी की जा सकती है और उसे जायज भी ठहराया जा सकता है। कुतर्कों के रिमोट से इसका चैनल कभी भी ट्यून किया जा सकता है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने राजनीतिक नैतिकता को ताक में रखकर इस सियासी मतांतरण के सफल प्रयोग कई राज्यों में किए हैं। यानी पहले विधायकों को तोड़ो, उसे या तो अलग गुट के रूप में मान्यता दिलाओ या फिर विधानसभा से इस्तीफा देकर अपने चुनाव चिन्ह पर लड़वा कर जिताओ या फिर 'आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा' की तर्ज पर सत्ता की सफारी में बिठा लो। इससे दो निशाने सधते हैं, पहला तो विरोधी पक्ष दोफाड़ हो जाता है, दूसरे साथ लाने और आने वाले दोनो की सत्ताकांक्षा की प्रतिपूर्ति होती है।

भाजपा का प्रयोग

भाजपा के इस प्रयोग को काफी हद तक मतदाता की भी स्वीकृति मिली है। एक और तीसरा तरीका यह है कि पहले तो विरोधियों को भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों व जांच के शिंकजे में कसो और बाद में पीले चावल भेज दो। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हुए शिंदे गुट और राकांपा से अलग हुए अजित पवार गुट की कुछ ऐसी ही कहानी है। दरअसल राजनीतिक विरोधियों के 'इलाज' का यह नुस्खा इसलिए शर्तिया साबित हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के हमाम में लगभग सभी नंगे हैं या यूं कहें कि अब भ्रष्टाचारियों में भी एक नए तरह का 'बंधुत्व' स्थापित हो गया है, जिसकी एकमात्र शर्त 'अपने खेमे' में होना है।

देश में इक्कीसवीं सदी की राजनीतिक नैतिकता का दूसरा पहाड़ा थूक कर चाटने का है। इससे भी शायद ही कोई बचा हो। 'समय की मांग' इस राजनीतिक रामबाण का 'एपीआई' (एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट, जो तमाम दवाइयों का कच्चा माल होता है)। अगर महाराष्ट्र का ही उदाहरण लें तो अजित दादा की प्रशासनिक क्षमता की तारीफ करने वाले देवेन्द्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री 'अजित पवार की असली जगह जेल में है', यह कहते नहीं अघाते थे।

अजित पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले में जांच भी बैठाई थी। उधर कल तक 'आखिरी सांस तक मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहूंगा', जैसी बनावटी शपथ लेने वाले अजित पवार अब भाजपा के साथ ही अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। कल तक काका शरद पवार को आदर्श मानने वाले भतीजे अजित को देश में नरेन्द्र मोदी से बेहतर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। नैतिक पलटूबाजी का यह फार्मूला जदयू, राजद, कांग्रेस, माकपा, शिवसेना इत्यादि कई दलों पर लागू होता है। जिनके लिए राजनीतिक दुश्मनी केवल रोमांचक वीडियो गेम से ज्यादा कुछ नहीं है।

वैसे अजित पवार के नाम एक रिकॉर्ड और है। वो प्रदेश के पांचवीं बार खुशी-खुशी उपमुख्यमंत्री बने हैं और वो भी सीएम बनने की अदम्य आस में। यह कुछ वैसा ही है कि जैसे बेटे की आस में बेटियां पैदा करते जाना। कहना मुश्किल है कि इस बार उनका डिप्टी सीएम बनना शुभ शकुन है या अपशकुन। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अजित दादा उपमुख्यमंत्री बने रहने के लिए अभिशप्त हैं। इस पर पूरा भरोसा न करें तो भी यह हकीकत है कि अजित दादा जिस भी सीएम के उपमुख्यमंत्री बने हैं, उसका राजनीतिक बेड़ा जरूर गर्क हुआ है। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हो या फिर उद्धव ठाकरे हो अथवा देवेन्द्र फडणवीस हों (जिनके साथ चंद दिनों के डिप्टी सीएम रहे)। अब वो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में पांचवी बार डीसीएम बने हैं। उसमें भी उन्हें वित्त मंत्रालय सबसे प्यारा है। ऐसे में सवाल शिंदे के सियासी भविष्य पर लग रहा है।

बहरहाल 'एकनाथ' और 'अजित' के सहारे देवेन्द्र तथा उनकी पार्टी जिस राजनीतिक संभावनाओं को बूझ रही है, वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी जीत का ऐसा राजनीतिक च्यवनप्राश है, महायुति नाम दिया गया है। सत्ता स्वार्थ पर टिकी यह महायुति कितनी कामधेनु साबित होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि महायुति के इस देसी ऑटो को चलाना भी आसान नहीं है। उधर काकाजी की भी उम्र की ढलान पर यह आखिरी सियासी अग्नि परीक्षा है यानी कि इस पार या उस पार...!

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिपुरोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

(साधक) इनको जानकर (इनके) अमृत गुणों से प्रसन्नता का अनुभव करते हुए, स्वपीठ (श्री चक्रपीठ) को (दुग्ध आदि से) तृप्त करते हुए महान् स्वर्गलोक में निवास करते हैं और त्रैपुर परमधाम में पहुँच कर (अपने को) कृतकृत्य अनुभव करते हैं। (आदिमूल विद्या का स्वरूप इस प्रकार है- यह) काम, योनि, काम कला, वज्रपाणि, गुहा, हसा, मातरिश्वा, अभ्र, इन्द्र, पुनः गुहा, सकला और माया आदि से यह विशिष्टरूपा यह विद्या (प्रवर्धमान हुई) है।

यहाँ आदि विद्या के संकेताक्षर प्रयुक्त हुए हैं। जो इस प्रकार हैं काम क, योनि ए, कामकला - ई. वज्रपाणि ल, गुहा ह्रीं, हसाह स, मातरिश्वा क, अभ्र ह, इन्द्र ल, सकलास, क, ल, माया ह्रीं। ये सभी वर्ण प्रणवात्मिका आदि विद्या के प्रतीक हैं। (आदि विद्या के छठे वर्ण (ह-शिवबीज), सातवें वर्ण (स-शक्तिबीज) और वह्नि सारथि (क-कामेश- बीज) इसके मूलत्रिक (ह,स,क) का जप करते हुए कथ्य रूप, कवि (क्रान्तदर्शी भूत, भविष्यत् और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालज्ञ) सदृश कामेश्वर की स्तुति करते हुए अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। (वह देवी) पुर, हन्त्रीमुख (ह-स-क), विश्वमातारूप, रवि-रेखा (आदित्य मंडल रूप), स्वर मध्य (ई, ओ रूप) आदि रूपों में विद्यमान बृहत्तिथि (निमेष से लेकर कल्पान्त तक) तथा पंचदशादि (पन्द्रह तिथियाँ, वार नक्षत्रादि) नित्य (देवता भाव को प्राप्त) सषोडशिक (सोलहवीं तिथि पूर्णिमा सहित) पुर मध्य (स्व अविद्या पर आधारित) रूपों को धारण करती है।

(रवि, चन्द्र आदि के) मण्डल से आविर्भूत सर्वांग सुन्दरी जिसका एक स्तनविम्ब एवं मुख नीचे की ओर है, के देहत्रय (स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर) रूपी गुहा में अवस्थित परमेश्वर की कला-कामकला का ध्यान करके योगी अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके स्वेच्छानुसार काममय हो जाता है, (पर काम्यफल) जन्म आदि का कारण होता है, इसलिए (उच्च वर्ण वाले मुमुक्षु को) सकाम उपासना नहीं करनी चाहिए।

क्रमशः ...

अनुच्छेद 370 के कट्टर आलोचक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी

ललित गर्ग

भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक चैतन्य महापुरुषों ने देश की माटी को प्रणम्य बनाने एवं कालखंड को अमरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं कीर्तिवान महान पुरुषों में भारत केसरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सश्रद्धा एवं गर्व से लिया जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में हुआ था। वे बैरिस्टर और शिक्षाविद थे तो कुशल समाज-राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि, नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1980 में यही भारतीय जनता पार्टी बन गई। वे भारत को एक हिन्दू राष्ट्र एवं स्व-संस्कृति के अनुरूप विकसित होते हुए देखना चाहते थे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। सचमुच! वह कर्मयोद्धा कर्म करते-करते कृतकाम हो गया।

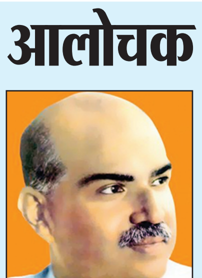

डॉ. मुखर्जी जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमन्त्री (वजीरे-आजम) अर्थात प्रधानमन्त्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में डॉ. मुखर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊँगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दूँगा। उन्होंने तात्कालिन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। डॉ. मुखर्जी ने यह नारा बुलंद किया कि 'एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे।' पं. प्रेमनाथ डोगरा की अगुवाई में प्रजा परिषद् के रूप में एक राष्ट्रवादी आंदोलन जम्मू-कश्मीर में आंधी की तरह छा गया। शेखशाही ने प्रदर्शनकारियों को खूब यातनाएं दी। इस पर मुखर्जी ने जम्मू जाने का निर्णय लिया। उनके परमिट के आवेदन को रद्द कर दिया गया। जिसके बाद परमिट का नियम तोड़ते हुए उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ 11 मई 1953 को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का निर्णय किया। उन्हें जम्मू में घुसते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उनके निजी डॉक्टर को उनके साथ नहीं आने दिया गया। 23 जून 1953 को कानूनी हिरासत में ही रहस्यात्मक ढंग से कश्मीर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके महाबलिदान ने हर भारतीय में प्रेरणा का ऐसा बीज बोया जो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने तथा अनुच्छेद 35-अ के हटने के साथ फलीभूत हुआ। उन्हीं के अथक परिश्रम व अतुलनीय बलिदान के कारण अंततः भारत देश में एक विधान, एक निशान एवं एक प्रधान का शासन लागू हुआ। भारत की एकता और अखण्डता को मजबूती देने एवं अखण्ड भारत के सपने को आकार देने वाले राष्ट्रवाद के सच्चे महानायक के रूप में डॉ. मुखर्जी का योगदान एवं बलिदान अविस्मरणीय रहेगा।

अमेरिका से बराबरी का बनता रिश्ता

डॉ अश्विनी महाजन

वैसे तो भारतीय प्रधानमंत्रियों की सभी यात्राएं मीडिया के लिए उत्सुकता और आकर्षण का विषय रहती रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा में, दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक निर्णयों, रणनीतिक खरीद, प्रौद्योगिकी सहयोग और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के स्वागत की काफी चर्चा हुई। इन दोनों महान लोकतंत्रों के रिश्ते इतिहास में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आज भी अमेरिका में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतंत्र आदि के फर्जी आख्यानों के आधार पर भारत पर उंगलियां उठाते रहते हैं। अतीत में ये तत्व सफल भी रहे हैं और आधिकारिक बयानों तथा कथनों आदि पर इसकी छाया देखने को मिलती रही है। लेकिन, पीएम मोदी की यात्रा की सफलता से पता चलता है कि शायद कूटनीतिक तौर पर यह पहले से तय था कि उनकी राजकीय यात्रा के दौरान वैसी कोई बयानबाजी नहीं की जायेगी।

भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष और दूरसंचार जैसी भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत और अमेरिका ने इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने का फैसला किया है। यह दो महान आर्थिक और प्रौद्योगिकी महाशक्तियों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का प्रकटीकरण है। आज अमेरिका आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्व भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है, जिसकी वर्तमान विश्व

अर्थव्यवस्था में भूमिका है। इतिहास में एक समय था जब अमेरिकी डॉलर सारी दुनिया पर हावी था, वैश्विक आरक्षित मुद्रा में डॉलर का हिस्सा 70 प्रतिशत था, आज वह घटकर लगभग 54 प्रतिशत रह गया है। अमेरिका इस समय सदी की सबसे ऊंची महंगाई दर को झेल रहा है।

अफगानिस्तान से अचानक सेना की वापसी और वहां कट्टरपंथी सरकार के उदय के बाद दुनिया के 'दादा' का दर्जा काफी घट गया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष में विफलता, यूक्रेन की लगातार हानि और परिणामस्वरूप ऊर्जा और बढ़ती मुद्रास्फीति के अलावा दुनियाभर में उत्पादन को प्रभावित करने वाली आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान ने, एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की कमजोरी को उजागर किया है। इन परिस्थितियों में, अमेरिका के लिए ऐसे साझेदार ढूंढना आवश्यक है जो सक्षम भी हो और भरोसेमंद भी। लोकतंत्र हमेशा से अमेरिका का मुख्य मुद्दा रहा है और अमेरिका जिस देश को अपना मुख्य शत्रु मानता है, उस चीन में निरंकुश शासन है। चीन का पड़ोसी और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, भारत संतुलन स्थापित करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। क्वाड के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग उस सोच का स्वाभाविक परिणाम है।

एक अमेरिकी राजनयिक का रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत के मध्यस्थ की भूमिका निभा सकने का हालिया बयान भारतीय नेतृत्व के बढ़ते दबदबे का संकेत है। अतीत में, अमेरिका महान और शक्तिशाली राष्ट्र के खुमार में जी रहा था। इसलिए भारत-अमेरिकी रिश्ते उस खुमारी से बाहर नहीं आ सके। पूर्व में हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में भारत के वाणिज्य मंत्री के समकक्ष स्थिति वाले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों (यूएसटीआर) का अहंकारपूर्ण रवैया भी देखा है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले यूएसटीआर के भारत आने-जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

गौरतलब है कि अतीत में भारत और अमेरिका के रिश्ते आमतौर पर असमान रहे हैं। रणनीतिक तौर पर अमेरिका ज्यादातर पाकिस्तान का समर्थक रहा है। कुल मिलाकर शीत युद्ध के समय से भारत और अमेरिका के रिश्तों में अगर कोई कड़वाहट नहीं थी, तो कोई अधिक सौहार्द भी नहीं था। लेकिन सोवियत संघ के पतन, चीन के आर्थिक उद्भव और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति के साथ भारत और अमेरिका के संबंधों में नये अध्याय जुड़े। वर्ष 2000 में, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया और नागरिक परमाणु सहयोग पर एक ऐतिहासिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये, जिसने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश में एक नया अध्याय खोला, और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई।

इस बार मोदी की यात्रा के दौरान जीइ कंपनी द्वारा फाइटर जेट के इंजन में ऐतिहासिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अमेरिका की पिछली नीति से बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, चीन के बढ़ते दबदबे और एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका को उसकी चुनौती के कारण भारत अमेरिका का स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड उसका एक स्वाभाविक परिणाम था।

पिछले करीब एक दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में नयी गर्माहट देखने को मिल रही है। भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार देश के रूप में उभरा है। यह समझना होगा कि भारत पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में, पहले 'मेक इन इंडिया' और बाद में 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत, भारत रणनीतिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इससे भारत का न सिर्फ रूस और अमेरिका समेत पश्चिम से रक्षा सामान का आयात कम हो रहा है, बल्कि वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रक्षा सामान का निर्यात भी करने लगा है। अंतरिक्ष, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग और भुगतान समेत विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध कुछ हद तक तनावपूर्ण हो गये थे। अब भारत और अमेरिका दोनों ने अपने आर्थिक हितों को देखते हुए अपने व्यापार विवादों को खत्म करने का फैसला किया है। इस बराबरी के समझौते को भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया अध्याय माना जा रहा है, जहां कोई भी फैसला एकतरफा नहीं होता।

बापू की दिनचर्या

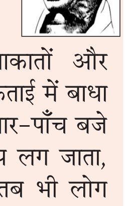

भेंट-वार्ता

सूत्र-यज्ञ के समय बापू का महत्त्वपूर्ण मुलाकातों और भेंटवार्ताओं का क्रम प्रायः चलता रहता। इससे उनकी कताई में बाधा नहीं पड़ती। लंदन में वे मिलने वालों को प्रायः प्रातः चार-पाँच बजे का समय देते। वहाँ पहुँचने में लोगों को काफी समय लग जाता, इसलिए लोगों को बहुत तड़के उठकर आना पड़ता, तब भी लोग पहुँचते। सूत्र यज्ञ के समय भी उनसे हर कोई मिल सकता। मुलाकातियों में सभी श्रेणियों के लोग होते। व्यक्ति और कार्य के अनुसार पहले बापू के सचिव उनके पास लोगों के संदेश पहुँचाते और समय निर्धारित कर उनसे भेंट कराते । सेवाग्राम में सन् 1936 से 46 के मध्य मिट्टी और देशी बल्लियों के छप्पर वाली बाहर-भीतर मिट्टी से लिपी अपनी कुटिया में बापू लोगों से मिलते। वहाँ खजूर की चटाइयाँ बिछी रहतीं। इन्हीं पर राजेंद्र बाबू, नेहरूजी, राजाजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अन्य बड़े नेता बैठा करते। सन् 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वहीं स्वीकृत हुआ । अंतिम दिनों में दिल्ली में मुलाकातियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने से जब बापू कभी-कभी बहुत थक जाते और प्रेमपूर्वक कहते- क्या और सारे काम बंद करके मुलाकातें ही करता रहूँ? और, उनके सचिव पूछते- तो क्या आज की मुलाकातें मुल्तबी कर दूँ? तब बापू तुरंत कहते-नहीं, जो आ गया, वह लौटकर क्यों जाए? आने दो उसे। लोग अपनी भाँति-भाँति की समस्याएँ, तरह-तरह के दुःख-दर्द लेकर पहुँचते। मंत्रियों के लिए मुलाकात का कोई समय निश्चित नहीं था, किसी समय पहुँच सकते। बापू अपने समय से अधिक महत्त्व उनके समय बे को देते। उनका कहना था कि उन्हें हुकूमत चलानी है न? अवकाश मिलने पर ही वे आ सकते हैं। जब दूसरों की मुलाकात के बीच कोई मंत्री पहुँच जाते तब लोगों को असुविधा अवश्य होती; फिर भी मुलाकातियों के लिए बापू समय निकाल लेते। कहने को मुलाकात के लिए घंटे-दो घंटे का समय रखा गया था, लेकिन प्रातःकाल से ही यह सिलसिला शुरू हो जाता।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पांच अलग-अलग गेट से प्रवेश करेंगे आम नागरिक

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को एक दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर आ रहे है। साइंस कालेज मैदान में होने वाली उनकी जनसभा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उनके प्रवेश के लिए 5 अलग-अलग गेट बनाया है जहां से वे मोदी को सुनने के लिए प्रवेश कर सकते है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के साथ साइंस कॉलेज मैदान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई और पीएम मोदी की सुरक्षा में आइजी रैंक के एक, तीन डीआइजी, दस एसपी, 20 एएसपी, 30 डीएसपी के साथ 1500 सुरक्षा बल के जवानों की वहां ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही डाग स्क्वाड, एडी स्क्वाड, एसपीजी का तगड़ा सुरक्षा घेरा भी रहेगा। एएसपी सिटी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि सभा स्थल पर आम जनता का प्रवेश पांच अलग-अलग गेटों से होगा। वहीं वीवीआइपी, वीआइपी, मीडिया कर्मियों के लिए अलग से गेट बनाने के साथ बैठक व्यवस्था की गई है।

आज आएंगे विजय जांगिड

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगिड गुरूवार को इंडिगो की नियमित विमान सेवा द्वारा सुबह 9 बजे नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 9.30 बजे सर्किट हाउस में कांग्रेसजनों से भेट एवं चर्चा। रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने रूद्राक्ष का पौधा रोपा

रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज रूद्राक्ष का पौधा रोपित कर राजीव गांधी मार्ग, वी.आई.पी. रोड में रायपुर नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण व हरीतिमा युक्त वातावरण बनाए रखने आयोजित वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। रायपुर नगर निगम द्वारा जन सहभागिता से आयोजित यह वृक्षारोपण कार्यक्रम रायपुर का सबसे लम्बा वन डे प्लांटेशन ड्राइव रहा, जिसमें जन सहभागिता से राजीव गांधी मार्ग, वी.आई.पी. रोड में राम मंदिर से फुंडहर चौक तक सड़क के दोनों ओर डिवाइडर पर 2.5 कि.मी तक वृक्षारोपण किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने इस वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए शहर को हरीतिमायुक्त बनाए रखने आम नागरिकों व विभिन्न संगठनों की भागीदारी से संचालित किए जा रहे सघन वृक्षारोपण अभियान के आयोजन पर रायपुर नगर निगम के पहल की सराहना की।

राज्यपाल ने कामधेनु विवि के कुलपति के लिए चयन समिति का किया गठन

रायपुर। राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) के धारा-9 के उप धारा (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग में कुलपति नियुक्ति हेतु पेनल अनुशंसित करने हेतु समिति का गठन किया है। राजभवन सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. बीजायान्द सिंह समिति के अध्यक्ष होंगे एवं डॉ. अय्याज एफ. तंबोली विशेष सचिव, छ.ग. शासन,कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और डॉ.सी.एस. प्रसाद पूर्व अस्सिटेंट डायरेक्टर जनरल उक्त समिति में सदस्य रहेंगे। यह समिति अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ- सप्ताह के अंदर न्यूनतम तीन व्यक्तियों का पेनल कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में आज राजभवन सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है।

मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा व आवेदन की तिथि बढ़ाई गई

रायपुर। पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग में संचालित एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी विषय की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की निर्धारित तिथि को बढ़ा दिया गया है अब इस विषय की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 25 जुलाई तक कर सकते हैं पहले यह तिथि 30 जून तक थी। नए सत्र में 10 उम्मीदवारों को प्रवेश हेतु आयोजित इस परीक्षा में एमबीबीएस, बीएससी लाइफ साइंसेस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीडीएस, बीपीटी इत्यादि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र हैं। प्रवेश परीक्षा अब 7 जुलाई के स्थान पर 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। मेरिट के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम में 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन चिकित्सा महाविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदेश में 10 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

रायपुर। प्रदेश में आगामी 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। राज्य के सात जिलों दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर-चाँपा, सक्ती, मुंगेली और महासमुंद में 10 अगस्त से 17 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै ने आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक लेकर दोनों अभियानों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मौजूद स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को दोनों अभियानों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को कहा। राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में दोनों अभियानों की रूपरेखा और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।

नवा रायपुर में होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार

सीएम बघेल ने की विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा

रायपुर। नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। लगभग 438.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा इस थोक बाजार का निर्माण किया जाएगा। यहां छोटे-बड़े सभी व्यापारियों के लिए आधारभूत जरूरी सुविधाएं होंगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा है कि इस थोक बाजार की कार्ययोजना को इस तरह से अमलीजामा पहनाएं ताकि देश का यह सबसे बड़ा थोक बाजार छोटे-बड़े सभी व्यापारियों की जरूरत पूरा कर सके। यहां व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का तीव्र विस्तार हो सके। बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य के निर्देश दिए।

सीएम ने की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने बैठक में नागरिक सेवाओं एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मितान योजना के क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की डिलीवरी बिना कार्यालय पहुंचे और शीघ्रता से नागरिकों को मिल पा रही है। मेरे पोते का आधार कार्ड भी मितान के माध्यम से बना है। मितान योजना पहले राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों में किया गया है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा आवेदन बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित आ रहे हैं। मितान योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश के नगर निगमों के 1 लाख 3 हजार 315 हितग्राहियों के विभिन्न दस्तावेज तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी की गई है। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए मितान को सबसे अधिक फोन आते है और यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही जाति और आय प्रमाणपत्र भी काफी बने हैं। नए नगरीय निकायों में मितान योजना आरम्भ होने के बाद 3 दिनों में लगभग 2 हजार कॉल आये हैं जिसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि फोन कॉल के साथ ही एप के माध्यम से भी मितान योजना की सेवा शीघ्र ही दी जाएगी।

सीएम ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ब घेल ने शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में कहा धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स बेहतर लोकेशन में खोले जाएं। उन्होंने इस मौके पर स्लम स्वास्थ्य योजना की समीक्षा की और लगातार हेल्थ कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए मौसमी बीमारियों से जुड़ी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से अब तक 132 करोड़ रुपये की बचत हितग्राहियों को हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन मेडिकल स्टोरों का लोकेशन भी बेहतर किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में एसएमएस के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जानकारी दिये जाने के प्रयासों पर काम हो रहा है। बैठक में अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन और शहरी आवास योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

रीपा के उत्पादों की ऑनलाइ न आपूर्ति व्यवस्था हो बेहतर

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) की समीक्षा में कहा कि सभी उत्पादों की ऑनलाइन आपूर्ति की व्यवस्था हो, सी-मार्ट में इनकी उपलब्धता हो। उत्पादनकर्ता को बाज़ार से जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि रीपा में अनेकों तरह की गतिविधि हो रही है। बेकरी एवं खाद्य उत्पाद, मिलेट, परिधान, निर्माण आदि क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है और उद्यमी आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय भवनों में रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग हो रहा है। निजी क्षेत्रों में भी इसकी बिक्री बढ़ाएं। उन्होंने रेरा में दर्ज बिल्डरों से भी गोबर पेंट के इस्तेमाल के लिए आग्रह करने अधिकारियों को कहा।

90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा

रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाई-फाई से डिजिटल कनेक्टीविटी अच्छी होने के कारण युवा भी इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वाई-फाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटली जुड़ने से इसका बड़ा लाभ सबको मिलेगा।

इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि संभाग स्तरीय मिलेट कार्निवाल के लिए योजना तैयार हो रही है। गोबर पेंट के उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। साथ ही रीपा के लिए तकनीकी सहायता हेतु सीएफटीआरआई में एक दल भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का संस्था से अनुबंध है, अतएव तकनीकी सहायता वहां से भी मिल सकेगी।

संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

■ **दीवाली के पहले शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर धमतरी ब्लॉक में मनाई जाएगी पानी की दीवाली**

रायपुर। संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डॉ. अलंग ने रायपुर संभाग में जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों और पेय जल व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संभाग के जिलों के अधिकारियों से जिले में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यो के संबंध में चर्चा की और योजना के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया ।

बैठक में संभागायुक्त ने रायपुर संभाग अंतर्गत सभी जिलों के कार्यों की समीक्षा की उन्होंने रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिले के प्रदर्शन को सहराते हुए अपनी खुशी जाहिर की साथ ही बालौदाबाजार जिले का प्रदर्शन राज्य के औसत प्रदर्शन से कम होने पर नाराज़गी भी व्यक्त की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों की सहराना करते हुए कहां यह अच्छी बात है कि सभी जिलों ने टेंडर के कार्य लगभग पूर्ण कर लिए है और इसलिए हम इस बैठक में टेंडर और ठेकेदारों की नहीं बल्की वास्तविक कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पानी की पाइप लाईन, प्लेटफार्म के निर्माण और कांक्रिट की गुणवक्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉ. अलंग ने बैठक में समीक्षा करते हुए पानी टंकी की निर्माण की गति धीमी होने पर नाराज़गी दिखाई साथ ही धीमे निर्माण के कारणों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए।

संभाग आयुक्त डॉ अलंग ने बैठक में अधिकारियों से चर्चा करते हुए यह बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल हर घर तक पानी पहुंचना ही नहीं बल्की घरों में जल संग्रहण के आदत को भी खत्म करना है। उन्होंने बैठक में धमतरी ब्लॉक में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर खुशी जाहिर कर अधिकारियों के प्रदर्शन को सराहा। साथ ही दीपावली के पूर्व लक्ष्य को शत् प्रतिशत पूरा कर ब्लॉक के हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की सफलता को पानी की दीवाली थीम के साथ उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने 80 से 90 प्रतिशत पूर्ण हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

नव निर्मित छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई के गोदाम से सम्बंधित शिकायतें पाई गई फर्जी

अंबिकापुर। खाद्य मंत्री मंत्री अमरजीत भगत ने बुधवार को बतौली विकास खंड के बेलकोटा में नव निर्मित गोदाम का औचक निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने अपने जन्मदिन के दिन 20 हज़ार मीट्रिक टन के इस गोदाम का उद्घाटन किया था। खाद्य मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत ने आज इस शिकायत और सुचना के आधार पर गोदाम का औचक निरिक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने पाया की शिकायत जितनी बड़ी थी उसके ठीक विपरीत वास्तविकता कुछ और ही है। गोदाम में छोटा सा रिसाव था जिसे दुरुस्त किया जा चूका है छोटी मोटी कमियां जो बारिश के उपरांत सामने आई उन्हें अधिकारीयों ने ठीक करा लिया है अब किसी प्रकार की कोई समस्या फिलहाल सामने नहीं है मंत्री ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि प्राप्त जानकारी के आधार पर आज मैंने बेलकोटा गोदाम का जांच किया जहां आरोप निराधार पाया गया कुछ छोटे-मोटे कमियां थीं जिन्हें दूर किया जा चुका है लेकिन बिना आधार कि इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके पश्चात मंत्री भगत बतौली के कन्या स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव व अन्य कार्यक्रमो में शामिल हुए। इस दौरान ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता,अरविन्द गुप्ता, अटल यादव, सुखिया मिंज सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और गोदाम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

पार्किंग और आवागमन का रूट मैप जारी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शासकीय कार्यक्रम एवं आम सभा कार्यक्रम का आयोजन होना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल होंगे।

यह है पार्किंग की व्यवस्था और रूट मैप: शासकीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शासकीय अधिकारियों के लिए मार्ग एवं पार्किंग- एनएचएआई व रेल्वे के शासकीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शासकीय अधिकारी गण जीई रोड से होकर आवागमन कर डीडीयू एडिटोरियमपार्किंग एवं यूनिवर्सिटी कैंपस पार्किंग में अपना वाहन पार्क करेंगे। भाजपा द्वारा आयोजित आम सभा में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के आवागमन हेतु मार्ग

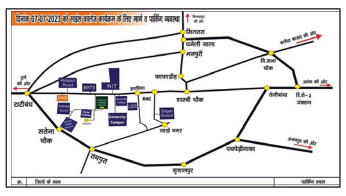

एवं पार्किंग- भाजपा के आम सभा कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं पदाधिकारी टाटीबंध की ओर से एवं रायपुर शहर की ओर से जीई रोड होकर आवागमन करेंगे एवं एनआईटी ग्राउंड, बीआरटीएस सिटीबस डिपो एवं क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पार्किंग में आपन वाहन पार्क करेगें। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आम सभा में सम्मिलित होने वाले आम नागरिकों एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के सुगम आवागमन हेतु निम्नानुसार मार्ग एवम् पार्किंग व्यवस्था बनाया गया है। उक्त कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी रायपुर की ओर आने वाले सभी मार्गों में भारी वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।बिलासपुर संभाग से होकर आने वाले आम नागरिक एवं भाजपा के सदस्य गण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से सिलतरा नया बाइपास रोड से टाटीबंध चौक से होकर तश्व रोड से सीधे NIT Ground पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेगें।दुर्ग संभाग से होकर आने वाले आम नागरिक एवं सदस्यगण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से होकर टाटीबंध चौक से जीई रोड होकर आयुर्वेदिक कॉलेज पार्किंग एवं सरोना चौक के पास पार्किंग में अपना वाहन पार्क करेंगे।बस्तर संभाग, धमतरी व अभनपुर से आने वाले आम नागरिक एवं सदस्यगण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से होकर पचपेड़ी नाका चौक से रिंग रोड नंबर 1 से होकर होकर भाटागांव चौक कुशालपुर चौक, रायपुरा अंडर ब्रिज से लाखे नगर चौक, आश्रम तिराहा, डगनिया रोड से ष्टस्श्वक्र मैदान पार्किंग एवं ईदगाह मैदान पार्किंग स्थल में अपना वाहन पार्क करेंगे।

गृहमंत्री साहू के विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला, हिंदू संगठनों ने रुकवाया कार्यक्रम

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब गरमाते जा रहा है। वहीं आरोप लग रहे हैं कि राज्य के गृहमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही धर्मांतरण का काम जोरों पर है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिंदू संगठनों ने विनायकपुर में धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आंदोलन किया था। जिसके तहत धर्म परिवर्तित कर चुके लोगों की फिर से हिंदू धर्म में वापसी कराई थी। वहीं अब एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जिसके कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

मामला तिरगा झोला गांव का है। हिंदू सगंठनों ने आरोप लगाया है कि ईसाई मिशनरियों ने इस गांव के लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया है। धर्म परिवर्तन की सूचना मिलते ही बजरंग दल, धर्मांतरण? मुक्त छत्तीसगढ़, विचार क्रांति अभियान ने मिलकर धर्मांतरण की कार्रवाई को रुकवाया। इस दौरान संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देकर ईसाई मिशनरियों के आयोजन को रद्द करवाया। साथ ही साथ गांव में मीटिंग करवाकर गांव वालों समेत आयोजकों को समझाईश दी गई।

हिंदू संगठनों ने की अपील- हिंदू संगठनों ने इस घटना के बाद गांव के लोगों से अपील की है कि, वो ससम्मान एक हफ्ते के अंदर अपने धर्म में वापस आ जाए। साथ ही साथ धर्मांतरण का विरोध करने की अपील भी संगठनों ने ग्रामीणों से की है। इसके बाद भी यदि ग्रामीण नहीं माने, तो एक हफ्ते बाद हिंदू धर्म में वापसी का अभियान चलाया जाएगा।

धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा- धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष लंबे समय से सरकार से सवाल कर रहा है। वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान और उसके बाद दी गई सफाई पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है और उसकी सरकार अपना ही खजाना लूटा है : चंद्राकर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पौने पांच साल में अरबों का घोटाला किया है, हम घोटाले की लिस्ट जारी नहीं करेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कल पत्रकारवार्ता के माध्यम से भाजपा के 15 साल के सरकार में एक लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया तो आज भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि अब तक जांच क्यों नहीं कराई। कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है और उसकी सरकार अपना ही खजाना लूटा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पौने पांच साल में अरबों का घोटाला किया है, हम घोटाले की लिस्ट जारी नहीं करेंगे।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता तथा राज्य के पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक शिवरतन शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल कभी पहले की सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करते बल्कि यदि कोई घोटाले हुए हैं तो उनकी जांच कराते हैं। कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है और उसकी सरकार

देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने अपना ही खजाना लूटा है। यदि भाजपा के शासनकाल में कोई घोटाले हुए तो जब 2003 में भाजपा की पहली सरकार बनी थी, उसके कुछ समय बाद से 2014 तक कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब यह कांग्रेसी क्या ताली बजा रहे थे? 10 साल में क्यों कोई जांच नहीं कराई गई? पौने 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इतने समय से क्या कर रहे थे? क्या मुजरा कर रहे थे? अगर मुजरा कर रहे थे तो भूपेश बघेल यह करना छोड़ें और स्वतंत्र जांच कराएं।

जिन घोटालों पर बात करते हो उनके बिंदुओं पर तथाकथित घोटाले में, जिन दो अधिकारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित मंत्रालय तक चिट्ठी लिखी, वे इस सरकार के लाडले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पौने पांच साल में अरबों रुपये का घोटाला किया है। हम भूपेश बघेल की तरह घोटाले की लिस्ट जारी नहीं करेंगे। मैं विधानसभा में कह चुका हूं कि इनकी जांच के बाद इनको जेल भेजेंगे। 2 अधिकारियों को क्या गुरुमंत्र लेने के लिए रखे हैं। वह सरकार में की पोस्ट पर हैं।

श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रियदर्शनी इंदिरा बैंक घोटाले की जांच हो रही है। उसके फाउंडर कौन थे। महिलाएं हैं इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा। भूपेश बघेल बताएं कि कौन-कौन से परिवार की महिलाएं हैं। कांग्रेस से संबंध रखती है कि नहीं रखती है? जिनके नाम उमेश सिन्हा ले रहे हैं, वे लोग जो गवाही में थे, क्या कांग्रेसी परिवार की महिलाओं के नाम सामने आएंगे? स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराएं। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल हो गई है यह तो आरंभिक जांच है। जो इसका सरगना बताया जाता है वह किस पार्टी का है? ऐसा स्थापित घोटाला कहीं नहीं हुआ। जो अपना ही खजाने लूट रही है। एक भाई प्रदेश को लूट रहा है एक भाई रायपुर को लूट रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे राजधानी से चुनावी शंखनाद

पीएम मोदी का 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर 7 जुलाई को रायपुर पहुंच रहे हैं। वह सुबह करीब 10.40 बजे रायपुर आएंगे और करीब 2 घंटे रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 12.40 बजे रायपुर से यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी जनता से जुड़े हाईवे, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस सभा को विजय संकल्प जनसभा का नाम दिया है।

रायपुर के साइंस कालेज मैदान में 7 जुलाई को पीएम मोदी की जनसभा के लिए बीजेपी जी जान से जुट गई है। हर गली और चौराहों पर बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। राजधानी के साथ ही पास पड़ोस के जिलों में प्रभात फेरी निकालते हुए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क किया जा रहा है। पीले चावल के साथ निमंत्रण कार्ड लोगों के घर घर पहुंचाया जा रहा है। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत भी रायपुर पश्चिम की गलियों में घूमकर लोगों को पीएम की सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। भाजपा के इस जनसंपर्क अभियान को देखते हुए लग रहा है मानो विधानसभा चुनाव साल के अंत में नहीं अभी शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा दृश्य आमतौर पर चुनाव के दौरान ही देखने को मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन में चार राज्यों का दौरा करेंगे। वह 7 और 8 जुलाई को चार राज्यों के 5 शहरों के दौरे पर रहेंगे। जिनमें रायपुर (छत्तीसगढ़), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), वारंगल (तेलंगाना), बीकानेर (राजस्थान) में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी दो दिन में सभी जगहों में मिलाकर कुल 50 हजार करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे।

उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी तीन राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा पीएम मोदी का यह दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम है। 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे। रायपुर में मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

छत्तीसगढ़ के बाद यूपी का दौरा- रायपुर से पीएम मोदी गोरखपुर जाएंगे, जहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर से पीएम मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां वह कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह एनएच 56 (वाराणसी-जौनपुर) के फोर-लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे।

पीएम मोदी का 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान दौरा- 8 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल जाएंगे। यहां वह नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वह वारंगल में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे।

पीएम मोदी 8 जुलाई को वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-फर्स्ट के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन भी समर्पित करेंगे। वह बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद वह बीकानेर में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री रायपुर में करीब 7500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 व 8 जुलाई को चार राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे की शुरुआत शुक्रवार सुबह पौने ग्यारह बजे रायपुर में कार्यक्रम से होगी। इससे पहले पीएम मोदी का रायपुर में पहुंचने का समय 9.40 था। लेकिन प्रधानमंत्री 10.30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 10.30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पीएम मोदी हेलीकाप्टर से सीधे जनसभा स्थल साइंस कालेज मैदान पहुंचेंगे। पीएम मोदी करीब दो घंटे रायपुर में रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री लगभग 6,400 करोड़ रूपए की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली परियोजनाओं में शामिल हैं - जबलपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर-कोडेबोड़ खंड की 33 कि.मी. लंबी 4 लेन वाली सड़क, आदि। पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, यह खंड, जगदलपुर के निकट स्थित इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की आवाजाही का अभिन्न अंग है और लौह अयस्क समृद्ध क्षेत्रों से परिवहन सम्पथर्क की सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री एनएच-130 के बिलासपुर-अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर-पथरापाली खंड पर निर्मित 4-लेन की सड़क का लोकार्पण करेंगे। यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच परिवहन सम्प्र्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित कोयला खदानों को परिवहन की सुविधा प्रदान करके कोयले की आवाजाही को बढ़ावा देगा।

प्रधानमंत्री 6-लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें शामिल है - एनएच-130 सीडी पर 43 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले झांकी-सरगी खंड का विकास; एनएच-130 सीडी पर 57 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले सरगी-बसनवाही खंड का विकास और एनएच-130 सीडी पर 25 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले बसनवाही-मारंगपुरी खंड का विकास। 2.8 किलोमीटर लंबी 6-लेन सुरंग एक प्रमुख घटक है - उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों के आसान आवागमन के लिए 27 रास्ते और 17 बंदर छतरियों का निर्माण। इन परियोजनाओं से धमतरी स्थित चावल मिलों और कांकेर के बॉक्साइट समृद्ध क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और इससे कोंडागांव के हस्तशिल्प उद्योग को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर, ये परियोजनाएं क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्सा हन प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री 103 किलोमीटर लंबी रायपुर-खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 750 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। इससे बंदरगाहों से छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए कोयला, इस्पात, उर्वरक और अन्य वस्तुओं का परिवहन आसान हो जाएगा। वे केवटी-अंतागढ़ को जोडने़ वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 290 करोड़ रुपये की लागत से विकसित नई रेलवे लाइन भिलाई स्टील प्लांट को दल्ली राजहरा और रावघाट क्षेत्रों की लौह अयस्क खदानों से परिवहन सुविधा प्रदान करेगी और घने जंगलों से होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री कोरबा में 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 60 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

रायपुर आने का समय बदला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सात जुलाई के दौरा प्रस्तावित है। अब इसके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री सुबह 9:40 बजे की जगह 10: 45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में साइंस कॉलेज ग्राउंड जाएंगे। इस दौरान रेल और सड़क से जुड़ी पांच केंद्रीय परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रभातफेरी निकालकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में करीब दो घंटे रहेंगे। इस दौरान करीब 7500 करोड़ की सौगात देंगे। दोपहर 12ः40 के आसपास रायपुर से यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के मुताबिक, इस सभा को विजय संकल्प जनसभा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी पहुंचेंगे। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रभातफेरी निकालकर दिया न्योता

रायपुर। दूसरी ओर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में रायपुर में प्रभातफेरी निकालकर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लोगों को आने के लिए न्योता दिया गया। बीजेपी जनता के बीच जाकर पीएम मोदी की आमसभा के लिए आमंत्रित किया। रायपुर पश्चिम विधानसभा के मोहल्लों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभातफेरी निकाली। प्रधानमंत्री 7 से 8 जुलाई को चार राज्यों के पांच शहरों का दौरा करेंगे। इनमें रायपुर (छत्तीसगढ़), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), वारंगल (तेलंगाना), बीकानेर (राजस्थान) शामिल हैं। इन सभी जगहों को मिलाकर लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की जनता को सौगात देंगे।

छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में होगा स्वागत, बन रहे तीन मंच

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि पीएम मोदी की सभा के लिए साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में तीन मंच बनाए जा रहे हैं। एक मुख्य मंच में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रमुख नेता बैठेंगे। दूसरा छोटा मंच प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया जा रहा है। वहीं तीसरा छोटा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रहेगा। बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। सभा स्थल पर वीआईपी, मीडिया और आम लोगों के पहुंचने के लिए 12 गेट बनाए जा रहे हैं। कड़ी जांच के बाद पंडाल में प्रवेश दिया जाएगा।

एसपीजी के साथ दो हजार जवान रहेंगे तैनात

आईजी अजय यादव ने बताया कि पीएम मोदी की सभा को लेकर शहर में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपीजी के साथ करीब दो हजार पुलिसजवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। डीजीपी अशोक जुनेजा पिछले दिनों बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हेलीपेड़ के पास लगाई गई है। 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल पर तैनात रहेंगे। 50 से ज्यादा एसपीजी के अधिकारी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए विभिन्न जिलों से एडिशनल एसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को भी राजधानी बुलाया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी आये या शाह 2023 में आयेगी तो कांग्रेस ही: मरकाम

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के पूर्व गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी आयें या शाह छत्तीसगढ़ में 2023 में आयेगी कांग्रेस ही जनता इस बात को भलीभांति समझ रही है कि मोदी को छत्तीसगढ़ की याद चुनाव में ही आती है। देश में यदि मोदी की सरकार है तो उसमें बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ से भाजपा के 9 सांसद है लेकिन पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। छत्तीसगढ़ के भले के लिये कोई निर्णय नहीं लिया। राज्य के हित में कोई योजना नहीं बनाई गयी। केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने में भी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गयी। कोरोना के समय देशभर में चलाई गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को वंचित रखा गया। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल होने के बावजूद तथा रामवनगमन का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बीतने के बावजूद रामायण सर्किट से छत्तीसगढ़ को वंचित रखा गया। छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास में विलंब के कारण कटौती कर दिया। छत्तीसगढ़ में तैनात केन्द्रीय सुरक्षाबलों पर लगने वाले 11000 करोड़ को छत्तीसगढ़ से वसूल लिया। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है।

यू-विन और मिशन इंद्रधनुष की दी गई जानकारी

रायपुर। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में जिलों में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को मिशन इंद्रधनुष 5.0 की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में टीकाकरण के उप संचालक तथा यूएनपीडी के टीम लीडर ने कार्यशाला में ऑनलाइन भागीदारी कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि राज्य में मिशन इंद्रधनुष 5.0 तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी छूटे हुए बच्चो का सर्वे एवं चिन्हांकन कर यू-विन प्लेटफॉर्म में पंजीकृत कर टीकाकरण किया जाएगा। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितम्बर से 16 सितम्बर तक और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का नेम बेस्ड ट्रैकिंग किया जा सकता है। इससे सभी बच्चों को समय पर टीका लगाने में सहायता मिलेगी।

यह भूपेश बघेल सरकार की सफलता है : धनंजय

रायपुर। भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की व्यवस्था और निमंत्रण पत्र में माता कौशल्या की धरा का उल्लेख होने पर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने

कहा कि यह भूपेश बघेल सरकार की सफलता है जो भाजपा 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विरोध करती थी आज वह भी जय छत्तीसगढ़ का नारा लगाने को मजबूर है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के संस्कृति, परंपरा, तीज, त्यौहार को कुचला गया था, माता कौशल्या को भुला दिया गया था। अस्तित्व पर संकट मंडराया तो भाजपा को माता कौशल्या और छत्तीसगढिया संस्कृति की याद आने लगी है, 15 साल तक भाजपा ने इधर झांका भी नहीं था।आज भाजपा कार्यालय को छत्तीसगढिया संस्कृति से सजाना और छत्तीसगढ़ी व्यंजन की व्यवस्था करना रमन सरकार के दौरान जो छत्तीसगढियों का जो अपमान हुआ था उसको छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। रमन सरकार के दौरान जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते थे तब उनके लिए नाश्ता में फाफड़ा और गुजराती व्यंजनों की व्यवस्था की जाती थी। आज भाजपा कार्यालय में अमित शाह के लिए छत्तीसगढ़ के व्यंजन ठेठरी खुरमी, चिल्ला, फरा सहित छत्तीसगढ़ी व्यंजन की व्यवस्था की जा रही है।

अजय, रमन सरकार के भ्रष्टाचार से ध्यान नहीं हटा सकते: शुक्ला

रायपुर। एक लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के जो आरोप भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार पर लगे है, आरोप प्रमाणिक और तथ्यों के साथ लगे है, भाजपा उसका जवाब दें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अशिष्ट

भाषा का प्रयोग करके भ्रष्टाचार से ध्यान नहीं हटाया जा सकता है। साहस है तो प्रधानमंत्री से कहकर नान, चिटफंड, शराब घोटाला, पनामा पेपर, गौशाला अनुदान घोटाला, इंदिरा बैंक घोटाला की ईडी से जांच करायें। यदि रमन सिंह सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच हो गयी तो पूरा रमन मंत्रिमंडल जेल के सलाखों के पीछे होगा। ईडी को भेजकर राज्य सरकार को बदनाम करने की पटकथा लिखने वाली भाजपा अपने घोटालों की सूची देख कर तिलमिला गयी है। जनता को इन घोटालों का हिसाब भाजपा को देना ही होगा।शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर भी अली बाबा चालिस चोर गिरोह के 15 साल सदस्य रहे है। इन घोटालों में वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते है। भ्रष्टाचार खुद करेंगे जब उनके भ्रष्टाचार की जांच की बात हो तो कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की बात करेंगे यह तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी इस गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भाजपा के रहमो करम पर नहीं चल रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जनता के द्वारा दिये गये दो तिहाई बहुमत से चल रही। भाजपा के तमाम षडयंत्रो के बावजूद पूरी मजबूती से चल रही।

राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था को चाक-चौबंद करने विशेष पहल

रायपुर। राज्य शासन द्वारा राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था को चाक-चौबंद करने विशेष पहल की गई है। राज्य स्तरीय अधिकारी जिलों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य स्तरीय अधिकारी अपने प्रभार वाले जिले में 5 अगस्त तक शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों और शासन की योजनाओं की आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारियों को जिले का आबंटन किया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार अधिकारी अपने आबंटित जिले में नए शिक्षा सत्र में विशेष तौर पर शालाओं में शिक्षकों की अनुपस्थिति या विलंब से उपस्थिति, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, प्रार्थना सत्र का क्रियान्वयन, निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर अनुसार अध्यापन कार्य, बैगलेस डे का पालन, समय-सारिणी अनुसार शाला का संचालन, नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयका संचालन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, सायकल की उपलब्धता सहित मध्यान्ह भोजन का नियमित क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर इनका पालन सुनिश्चित करवाएंगे। शैक्षणिक संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक जे.पी. रथ को कोरबा, उप संचालक आशुतोष चावरे को दुर्ग, उप संचालक राकेश पांडेय को दंतेवाड़ा, उप संचालक करमन खटकर को बलौदाजार-भाटापारा।

असौंदा में महिलाओं ने सम्हाला शराब विरोधी मोर्चा

रायपुर। अवैध शराब बिक्री से त्रस्त ग्राम असौंदा के ग्रामीणों की बीते रविवार को आयोजित बैठक में ग्रामीणों की एकजुटता व नजदीकी ग्रामों के समर्थन से उत्साहित महिलाओं ने ग्राम में शराब विरोधी मोर्चा सम्हाल लिया है। रविवार शाम से ही वे ग्राम के गली - कूचों में भ्रमण कर कोचियो को समझाईश देने के साथ-साथ बुड़ेनी के महिलाओं के तर्ज पर चौकसी कर रहे हैं। फिलहाल ग्राम में अघोषित भट्ठी का माहौल तो बंद हो चला है पर कतिपय कोचियो द्वारा अब भी चोरी छिपे शराब बेचने की शिकायत है जिस पर ग्रामीणों की नजर है। असौंदा के ग्रामीणों ने आसपास के ग्रामों के पियक्कड़ों को असौंदा का रुख न करने की सलाह दी है। ज्ञातव्य हो कि ग्राम असौंदा में सक्रिय 8-10 कोचियो ने ग्राम में अघोषित भट्ठी का माहौल बना रखा था।

इसकी वजह से न केवल असौंदा के आम ग्रामीण वरन् असौंदा के सड़क मार्ग से गुजरने वाले आसपास के ग्रामों के ग्रामीण भी हलाकान थे। प्रभावित आसपास के ग्रामों के ग्राम प्रमुखों व असौंदा के ग्रामीणों व खासकर महिलाओं के आग्रह पर बीते रविवार को पंचायत द्वारा शराब विरोधी मोर्चा खोलने बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में ग्रामीणों की एकजुटता व सक्रिय सहयोग के आश्वासन से उत्साहित महिलाओं ने बैठक के तुरंत बाद ही ग्राम प्रमुखों व आमंत्रित आसपास के ग्रामों के ग्राम प्रमुखों के साथ ग्राम के गली कूचों से घूम शराब कोचियो को शराब बेचने से तौबा कर लेने की नसीहत दी थी। इसके बाद से वे रोजाना रैली निकाल चौकसी भी कर रही हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ग्राम में चलने वाले अघोषित भट्ठी का? माहौल ग्रामीणों की एकजुटता को देखते हुये फिलहाल बंद दिख रहा है लेकिन ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब भी 1 - 2 शराब कोचिये गुपचुप तरीके से शराब बेचने से बाज नहीं आये हैं। वे अपने खास ग्राहकों सहित बाहरी ग्रामों से आने वाले पियक्कड़ों को गुपचुप तरीके से शराब मुहैय्या करा रहे हैं जिस पर ग्रामीणों की नजर है। इधर 2 - 3 दिनों के प्रयास व ग्रामवासियों से मिल रहे व्यापक सक्रिय जनसमर्थन व इसकी वजह से ग्राम में व्याप्त हो रहे शांति से आल्हादित महिलाये इस अभियान में और कसावट लाने की तैय्यारी कर रही हैं। सरपंच राजेश साहू , पूर्व सरपंचद्वय जितेन्द्र चंद्राकर व राजू टंडन सहित ग्राम प्रमुखों व महिलाओं ने बाहरी ग्रामों से आने वाले पियक्कड़ों को असौंदा की ओर रुख न करने की नसीहत देते हुये अवहेलना करने पर ग्रामीण आक्रोश का सामना करने व इसके लिये ग्राम प्रमुखों के जिम्मेदार न होने के प्रति आगाह किया है।

सीएसआईडीसी अधिकारियों की साय ने ली बैठक

रायपुर। नंदकुमार साय ने छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उद्योग भवन में सीएसआईडीसी के अधिकारियों की बैठक ली और राज्य में औद्योगिक प्रगति के संबंध पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा की मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए सतत कार्य करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की अधिक से अधिक स्थापना हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष श्री साय ने स्थानीय कृषि, खाद्य, लघु वनोपज, औषधीय वनोपज एवं हर्बल उपज पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के जड़ी-बूटी संबंधी प्राचीन ज्ञान के आधार पर स्थानीय औषधियों एवं हर्बल उपज पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना से उनका मूल्य संवर्धन संभव हो सकेगा एवं इसका लाभ सभी हो मिलेगा। अध्यक्ष श्री साय ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो रहे फूड पार्कों की स्थापना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।बैठक में संचालक उद्योग सह प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी डॉ. सारांश मित्तर ने अध्यक्ष श्री साय को राज्य में फूड पार्को, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एवं प्लास्टिक पार्क के निर्माण के लिए किए जा रहे अधोसंरचना विकास के बारे में बताया।

पॉवर कंपनी में "स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा दक्षता सुधार " पर प्रशिक्षण आयोजित

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी कर्मियों में दक्षता सुधार को ध्यान रखते हुए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ प्राकृतिक चिकित्सक एवं विपश्यना के आचार्य श्री सीताराम साहू ने प्रशिक्षणार्थियों को स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए तन और मन के पोषण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के नियम अचूक एवं अटूट हैं। यदि तन एवं मन में विकार होता है तो प्रकृति दण्ड देती है जो कि रोग, दु:ख एवं बेचैनी के रूप में सामने आता है। तन के विकार को दूर करने के लिये प्राकृतिक चिकित्सा एवं मन के विकार को दूर करने के लिये विपश्यना ध्यान कारगर उपाय है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,गुढ़ियारी में विगत दिवस आयोजित सात्विक पद्धति द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन विषयक कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता श्रीमती मधुलिका मिंज, कार्यपालन अभियंता श्री पी.बी. बंजारे एवं श्री एस. आर. साण्डे सहित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों के विभिन्न कार्यालयों के 50 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

योग प्रशिक्षक श्री साहू ने दक्षता में कमी के लिए शारीरिक रोग, मानसिक रोग, सजगता की कमी, समय की बर्बादी, तनाव ,आलस्य प्रमाद तथा अनियमित जीवन को बड़ा कारण बताया। उन्होंने 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर में सम्मिलित होने का भी सुझाव प्रतिभागियों को दिया। उन्होंने बताया कि इससे विचार-व्यवहार में सकारात्मक सुधार होता है। कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। श्री सीताराम साहू ने प्रतिभागियों को दक्षता सुधार में उपयोगी सहज स्वाभाविक श्वांस के आधार पर आनापान ध्यान का अभ्यास करवाया तथा जानकारी दी कि थोड़ी देर के आनापान के अभ्यास से बेचैनी दूर होती है, मन मजबूत होता है तथा याददाश्त तेज होता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.